



राष्ट्र के नाम संबोधन

नारी सब भूल जाती है मगर अपना अपमान नहीं भूलती: पीएम मोदी



नई दिल्ली। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े 131वें संविधान संशोधन विधेयक के पारित न हो पाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नारी सब कुछ भूल सकती है, लेकिन अपना अपमान नहीं भूलती, और इस संदर्भ में महिला आरक्षण बिल के गिरने को गंभीर घटना बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो सका। उन्होंने इस विधेयक के पारित न होने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कुछ दलों ने अपने स्वार्थ को देशहित से ऊपर रखा, जिसके कारण यह महत्वपूर्ण बिल पारित नहीं हो पाया।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस विधेयक के माध्यम से देश की नारी शक्ति को नई दिशा देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन विपक्ष के रूख के कारण यह प्रयास अधूरा रह गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सपनों और उनकी प्रगति की राह में रुकावट आई है, जिसे लेकर सरकार गंभीर है। प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं से क्षमा याचना करते हुए कहा कि यह प्रयास अपेक्षित परिणाम तक नहीं पहुंच सका। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में इस दिशा में प्रयास जारी रहेंगे।

लोकसभा में इस संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी। सदन में कुल 528 वोट पड़े, जिनमें से 298 वोट बिल के पक्ष में आए, जबकि इसे पारित करने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। इस प्रकार 54 वोटों की कमी के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका। इस घटनाक्रम के बाद संसद परिसर में भी विरोध देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया और विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि महिलाओं के अधिकारों से जुड़े इस मुद्दे पर राजनीतिक बाधाएं नहीं आनी चाहिए थीं।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर हार नहीं मानी है। उन्होंने संकेत दिया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इस विधेयक को पारित कराने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने कहा था कि इस विषय पर आगे भी प्रयास जारी रहेंगे। महिला आरक्षण को लंबे समय से देश में एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता रहा है, जिसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। इस विधेयक के पारित न हो पाने के बाद अब यह विषय फिर से राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर मतभेद खुलकर सामने आए हैं और आने वाले समय में इस पर और चर्चा होने की संभावना है। फिलहाल प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाशने की तैयारी में है।

ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य फिर कभी बंद न करने पर सहमत: ट्रंप

वाशिंगटन/ तेहरान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को दावा किया कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर कभी बंद न करने पर सहमत हो गया है जबकि ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखता है तो वह जलडमरूमध्य को बंद कर देगा। श्री ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, अब इसका (होर्मुज का) इस्तेमाल दुनिया के खिलाफ हथियार के रूप में नहीं किया जाएगा। दुनिया के लिए एक महान और शानदार दिन। दूसरी ओर, ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बार गालिबाफ ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से आवागमन तेहरान की अयमति से ही होगा। ईरान की यह चेतावनी श्री ट्रंप के उस बयान के कुछ घंटों बाद आयी है, जिसमें उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा था कि होर्मुज जलडमरूमध्य 'पूरी तरह से खुला' है और व्यापार के लिए तैयार है, लेकिन ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी। श्री ट्रंप ने यह भी दावा किया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होर्मुज जलडमरूमध्य के खुलने से 'बहुत खुश' हैं।

महिला आरक्षण बिल पारित न होना लोकतंत्र की बड़ी जीत: प्रियंका

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा ने महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं होने को लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया है। श्रीमती प्रियंका गांधी शनिवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने और देश के संघीय ढांचे में बदलाव की साजिश कर रही थी, जिसे विपक्ष ने मिलकर विफल कर दिया। उन्होंने कहा, यह संविधान की जीत है, देश की जीत है और विपक्ष की एकता की जीत है। सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर यह साफ दिख रहा था कि उन्हें बड़ा झटका लगा है। उन्होंने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने संकेत दिया था कि यदि विपक्ष सहमत नहीं होगा तो वह कभी चुनाव नहीं जीत पाएगा। इन बयानों से ही सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती है।



कांग्रेस की सामंती मानसिकता उजागर हुई: स्मृति

नईदिल्ली।भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उस पर महिलाओं के साथ धोखा करने और विधानसभाओं में 2029 से महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने और लोकसभा की संख्या बढ़ाने के लिए लागू गए संविधान संशोधन विधेयक के निचले सदन में खारिज होने पर उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं की हार का जश्न मनाने का आरोप लगाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाया कि वे दशकों से विभिन्न दलों की महिला नेताओं द्वारा राजनीति में संघर्ष किया।



तमिलनाडु में परिवारवाद और भ्रष्टाचार खत्म होगा: गोयल

नईदिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम (डीएमके) सरकार पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया और विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) 4 मई को अगली सरकार बनाएगा। ऊटी दौरे के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि 4 मई को तमिलनाडु की जनता की सेवा के लिए एक नई सरकार बनेगी। स्टालिन परिवार का भ्रष्टाचार डूबे यह एक परिवार का शासन डूबे शराब और जमीन के भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। राज्य में रिश्तखोरी व्यापक हो गई है, और कहा कि अगर आज तमिलनाडु में युवा लड़के-लड़कियां सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो उन्हें रिश्त देनी पड़ती हैं। यह जनता को स्वीकार्य नहीं है, और वे कभी भी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे जो तमिल संस्कृति विरोधी, तमिल महिलाओं विरोधी हो और रिश्तखोरी को बढ़ावा देता हो। हम उदयनिधि स्टालिन को डीएमके के भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में स्वीकार नहीं करते।



राहुल पर एफआईआर का अपना आदेश हाईकोर्ट जज ने बदला

नईदिल्ली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने के अपने पूर्व निर्देश पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई भी निर्णय आरोपी पक्ष को सुने बिना नहीं लिया जा सकता, यह मामला 2003 में ब्रिटेन में एक कंपनी बनाने के दौरान कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने के अपने पूर्व निर्देश पर रोक लगा दी। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, न्यायालय ने यह भी कहा कि आरोपी की सुनवाई के बिना कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। एक दिन पहले, उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कांग्रेस सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2003 में इंग्लैंड में एक कंपनी का गठन करते समय ब्रिटिश नागरिकता छिपाई थी।



सौरभ वर्णाय

नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ऐसा क्या है? जिसे विपक्ष समझ नहीं रहा और पक्ष समझ नहीं पा रहा? 16 अप्रैल से शुरू हुए संसद के इस विशेष सत्र के दूसरे दिन संसद में गर्मांगम बहस जारी है। सभी पार्टी के मुखिया मुखर होकर इस महिला आरक्षण: नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू कराना चाहते हैं लेकिन इसके साथ आए दो अन्य बिलों पर उन्हें खासकर विपक्ष को आपत्ति है जिस पर ऐसा लगा रहा है कि विपक्ष समझ नहीं रहा और पक्ष समझ नहीं पा रहा आखिर क्यों?

भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लाया

गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लंबे समय से लंबित था, जिसे अब संवैधानिक रूप देने की कोशिश हुई है। लेकिन इस कानून को लेकर जितनी सहमति दिखनी चाहिए थी, उतनी नहीं दिख रही। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है जिसे विपक्ष समझ नहीं पा रहा—या सत्ता पक्ष समझ नहीं पा रहा?

असल विवाद की जड़ कि विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि यह आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा। इसे जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया

गया है। यानी जब तक नई जनगणना और उसके बाद सीटों का पुनर्निर्धारण नहीं होगा, तब तक आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। विपक्ष का यह भी तर्क है कि यह एक टालू प्रावधान है—एक ऐसा वादा जो भविष्य में कहीं लागू होगा, पर अभी नहीं।

वहीं, सरकार का कहना है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत परिसीमन आवश्यक है, इसलिए यह तकनीकी अनिवार्यता है, न कि राजनीतिक टालमटोल। असल में यही वह बिंदु है जहां समझ का अंतर सबसे ज्यादा है—विपक्ष इसे राजनीतिक देरी मानता है, जबकि पक्ष इसे संवैधानिक आवश्यकता



के रूप में प्रस्तुत करता है। ओबीसी आरक्षण का सवाल—अधूरा प्रतिनिधित्व? विपक्ष, खासकर सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले दल, यह सवाल उठा रहे हैं कि महिलाओं के भीतर भी वर्गीय और जातीय असमानताएं हैं। वे मांग कर रहे हैं कि 33

प्रतिशत आरक्षण के भीतर ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा होना चाहिए। सरकार इस पर स्पष्ट प्रावधान नहीं लाई है। यहीं विपक्ष को लगता है कि यह अधिनियम समावेशी नहीं, बल्कि सामान्यीकृत है। यह मुद्दा सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि

सामाजिक प्रतिनिधित्व का है—जिसे सत्ता पक्ष अभी पूरी तरह संतोषजनक तरीके से समझ नहीं कर पाया है। अधिनियम ऐसे स्पष्ट लाया गया जब चुनावी माहौल बन रहा है। विपक्ष इसे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश के रूप में देखता है, जबकि सरकार इसे महिलाओं के सशक्तिकरण

का ऐतिहासिक निर्णय बता रही है। यहां समस्या नीयत की है—जिसे कानून से ज्यादा राजनीति प्रभावित कर रही है। असल संकेत शायद समझ का नहीं, बल्कि संवाद का है। सरकार ने इसे उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन विस्तृत बहस और सहमति बनाने की कोशिश सीमित रही। विपक्ष ने भी रचनात्मक सुझाव देने के बजाय कई बार इसे पूरी तरह खारिज करने का रुख अपनाया। नतीजा यह हुआ कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार राजनीतिक अविश्वास का शिकार हो गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अपने उद्देश्य में निस्संदेह प्रगतिशील है, लेकिन उसकी संरचना और कार्यान्वयन को

लेकर जो अस्पष्टता है, वही विवाद की असली वजह है। अगर सत्ता पक्ष इसे केवल ऐतिहासिक उपलब्धि बताने के बजाय उसकी समस्यासीमा और समावेशिता पर स्पष्टता लाए, और विपक्ष भी केवल विरोध के बजाय ठोस सुधार सुझाए—तो यह कानून वास्तव में भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी का नया अध्याय लिख सकता है। परिसीमन बिल पर आपत्तियां: भारत में जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया, जिसे परिसीमन कहा जाता है, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को अधिक न्यायसंगत बनाने का एक अहम उपकरण है।

महिला आरक्षण: समझ का संकट या संवाद की कमी

बंदूक से विकास की ओर, सुकमा के तुंगल इको-पर्यटन केंद्र की प्रेरक कहानी

सुकमा। जिले में वन विभाग की एक सराहनीय पहल ने विकास और पुनर्वास की नई मिसाल पेश की है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में तैयार किया गया तुंगल इको-पर्यटन केंद्र आज आत्मनिर्भरता और सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन गया है। सुकमा नगर से मात्र एक किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान पहले उपेक्षित और जर्जर था, लेकिन वन विभाग के प्रयासों से इसे एक सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया। यहाँ बनाए गए आकर्षक टापू और प्राकृतिक वातावरण अब स्थानीय लोगों के साथ-साथ पड़ोसी राज्य ओडिशा से आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहे हैं।

इस केंद्र की सबसे खास पहल है तुंगल नेचर कैफे, जिस ‘आत्मसमर्पण पुनर्वास महिला स्वयं सहायता समूह’ की 10 महिलाएँ संचालित कर रही



हैं। इनमें 5 महिलाएँ वे हैं जिन्होंने नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया है, जबकि 5 महिलाएँ नक्सल हिंसा से प्रभावित रही हैं। इन सभी को जगदलपुर और सुकमा के संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार किया गया है। आज ये महिलाएँ आत्मविश्वास के साथ पर्यटकों का

स्वागत कर रही हैं और सम्मानजनक जीवन जी रही हैं। जो महिलाएँ कभी संघर्ष और भय के माहौल में थीं, वे अब स्वावलंबन और आत्मसम्मान की मिसाल बन गई हैं। इस पर्यटन केंद्र की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 31 दिसंबर 2025 को शुरू होने के बाद केवल तीन

महीनों में, 30 मार्च 2026 तक यहाँ 8 हजार 889 पर्यटक आए। इस दौरान केंद्र ने लगभग 2.92 लाख रूपए की आय भी अर्जित की। पर्यटक यहाँ स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेने के साथ-साथ तुंगल डैम में कयाकिंग, पैडल बोटिंग और बॉस राफ्टिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का भी अनुभव कर रहे हैं। यह पहल साबित करती है कि सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर जीवन की दिशा बदली जा सकती है। तुंगल इको-पर्यटन केंद्र न केवल पर्यटन का केंद्र है, बल्कि यह उन महिलाओं के साहस, आत्मविश्वास और वन विभाग की दूरदर्शी सोच का प्रतीक है। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि प्रकृति संरक्षण के साथ-साथ मानव विकास को जोड़कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

बलरामपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों को सड़क से जोड़ा

बलरामपुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत 58 सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास कार्यक्रम जिला मुख्यालय के ऑडिटोरियम भवन में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पहले बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों को सड़क से जोड़ा गया। योजना के फेस 4 में बचे बसाहटों को बारह मासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बलरामपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए 58 सड़कों की स्वीकृति मिली है। लगभग 142 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इन सड़कों का शिलान्यास और भूमिपूजन शुक्रवार को किया गया। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और विकास को नई



मिलेगी। पीएमजीएसवाय के कार्यपालन अभियंता सच्चिदानंद ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2025-26 में फेस 4 के प्रथम चरण में कुल 58 सड़कों का निर्माण स्वीकृत हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 142।55 किलोमीटर एवं लागत लगभग 140।8 करोड़ है। इन सड़कों के निर्माण से 58 नवीन बसाहटें अब पक्की सड़कों से जुड़ेंगे जिससे वर्ष भर आवागमन सुगम होगा।

नगर पालिका के विवादित सीएमओ प्रणव राय का आखिर हुआ तबादला

बलरामपुर। नगर पालिका में लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच आखिरकार राज्य शासन ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रणव राय का स्थानांतरण कर दिया है। यह कार्रवाई उनके खिलाफ लगे गंभीर आरोपों और बढ़ते जनप्रतिनिधियों के विरोध के बाद की गई है। दरअसल, प्रणव राय पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने और पार्षदों को धमकाने के आरोप लगे थे। मामले ने उस समय तुल पकड़ लिया, जब एक कथित कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस रिकॉर्डिंग के सामने आने के बाद नगर पालिका की राजनीति और प्रशासनिक माहौल काफी गर्म हो गया था। भाजपा के कई पार्षदों ने खुलकर सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और उनके व्यवहार को

लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी। पार्षदों का आरोप था कि सीएमओ का रवैया जनप्रतिनिधियों के प्रति अपमानजनक रहा है, और इससे कामकाज भी प्रभावित हो रहा था। इस संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों और शासन स्तर पर शिकायतें भी की गई थीं। लगातार बढ़ते विवाद और जनप्रतिनिधियों में नाराजगी को देखते हुए अंततः राज्य शासन ने मामले में हस्तक्षेप किया। इसके बाद विवादित सीएमओ प्रणव राय का बलरामपुर नपा से तमनार नगर पालिका में स्थानांतरण कर दिया है। पार्षदों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शासन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि अब नगर पालिका में कार्य व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सकेगी।

खुद पर पेट्रोल डालने वाला युवक 80 प्रतिशत झुलसा

बिलासपुर। बिलासपुर जिले में एक युवक ने बीच सड़क पर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा लिया। जिससे वो 80व तक झुलस गया है। बर्न और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना का लाइव सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। मामला बिल्हा थाना क्षेत्र का है। वीडियो में दिख रहा है कि, युवक पेट्रोल पंप से डिब्बे में पेट्रोल खरीदता है। उसके बाद बाइक पर रखकर सड़क पर आ जाता है। अचानक बीच सड़क पर रुका, फिर खुद पर तेल डालकर माचिस मार लिया। आग से लिपटा युवक चीखते-चिल्लाते हुए 20 मीटर तक भागा और जमीन पर लोटने लगा। कुछ स्थानीय लोग उसे देखकर तुरंत मौके पर पहुंचे और आग

बुझाई। हालांकि, पुलिस को दिए बयान में युवक ने इसे हादसा बताया है। लेकिन वीडियो भी वो खुद आग लगाते दिख रहा है। इसलिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक, ग्राम पोशरी निवासी मनजीत जायसवाल (28) पिता लेखराम जायसवाल ने शुक्रवार को दोपहर 2.33 बजे पेट्रोल पंप से डिब्बे में पेट्रोल खरीदा। इसके बाद अपनी मोटोरेट से कुछ दूरी तक गया और सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एंबुलेंस को मदद से उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया।

बंगाल चुनाव, बिलासपुर जोन से चलेंगी 16 स्पेशल ट्रेनें रद्द ट्रेनें हुई बहाल

बिलासपुर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अब महज एक सप्ताह बचा है। ऐसे में दूसरे राज्यों में काम करने गए वोटर्स की आवाजवाही को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। बिलासपुर जोन से होकर कुल 16 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें कुछ ट्रेनें समर वेकेशन के नाम पर पहले ही शुरू हो चुकी हैं, जबकि ज्यादातर ट्रेनें मतदान से 2 से 4 दिन पहले चलाई जाएंगी। हालांकि, रेलवे ने आधिकारिक तौर पर इन ट्रेनें को चुनाव से नहीं जोड़ा है, लेकिन इसकी टाइमिंग को देखते हुए इसे चुनाव से जोड़कर चला जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है। दरअसल, रेलवे की समर स्पेशल ट्रेनों का फोकस पश्चिम बंगाल रूट पर ज्यादा है। बड़ी संख्या में

वहां के लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में रहते हैं। ऐसे में इन ट्रेनों को मतदाताओं की सुविधा से जोड़कर देखा जा रहा है। रेलवे ने उन शहरों को फोकस किया है, जहां बंगाल, असम और दक्षिण भारत के श्रमिक और मध्यम वर्गीय वोटर बड़ी संख्या में रहते हैं। पुणे-पुलटोटी-वलसाड रूट यहां से सांतरागाछी और खड़गपुर के लिए विशेष ट्रेनें दी गई हैं, ताकि महाराष्ट्र और गुजरात में रहने वाले वोटर समय पर पहुंच सकें। दुर्ग-गोंदिया-इतवारी- बिलासपुर जोन की ये तीन प्रमुख ट्रेनें स्थानीय स्तर पर बंगाल जाने वाले यात्रियों के लिए लाइफलाइन बनेंगी। पटना-रक्सौल कॉरिडोर इन ट्रेनों के जरिए मालदा, दिनापुर, वीरभूम और हल्दिया जैसे संवेदनशील चुनावी इलाकों के वोटर्स को टारगेट किया।

प्राइवेट स्कूलों पर मनमानी फीस बढ़ोतरी का आरोप

अभिभावक बोले नियमों के बाद भी असर नहीं

सरगुजा। हर साल जब स्कूलों का नया सेशन शुरू होता है तब प्राइवेट स्कूलों की फीस का मामला उठता है लेकिन इसके बाद इस विषय पर वर्ष भर कोई बात नहीं होती है, सरकार शिक्षा विभाग को आदेश जारी करता है। शिक्षा विभाग भी आदेश को अनुपालन में एक आदेश जारी कर देता है, लेकिन क्या वाकई स्कूलों पर फीस निर्धारण का कोई सरकारी नियंत्रण काम करता है। फिर मनमाने ढंग से निजी स्कूल फीस वसूल रहे हैं। हमने कुछ अभिभावक, अभिभावक संघ के लोगों से बात की तो उनका सीधा आरोप है कि फीस के नाम पर मोटी रकम वसूलने का काम हो रहा है।



अभिभावक संघ से जुड़े धनंजय के मुताबिक फीस बढ़ोतरी की मनमानी आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से हो रही है, मेरा बच्चा तो काफी बड़े क्लास में पहुंच गया लेकिन जब वो नर्सरी में था तब से लेकर लगातार मनमानी देख रहा हूं। हम लोगों ने अभिभावक संघ के माध्यम से कई बार आवाज भी उठाई है। लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है।

अभी वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। जिसमें पोर्टल में ऑनलाइन शिकायत करने की बात भी कही जा रही है। लेकिन कोई भी पेरेंट्स शिकायत करने नहीं आएगा। आज तक कभी नहीं आते हैं सामने, क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला होता है।

अभिभावक संघ के संरक्षक निलेश सिंह के मुताबिक इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने जिस समय गाइडलाइन जारी किया था यदि उसका सही समय पर पालन हुआ होता और ये सुनिश्चित करने के लिए कोई टीम गठित कर दी गई होती कि समय पर इसका पालन हुआ या नहीं तो निश्चित रूप से उस पर एक बड़ी कसावट आपको देखने को मिलती। लेकिन समय के बाद जब पेरेंट्स बच्चों का एडमिशन करवा चुके हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी का एक्टिव होना कोई मायने नहीं रखता। अभिभावक सूर्य नारायण के मुताबिक आज छत्तीसगढ़ में शिक्षा माफिया

बेलगाम हैं ऐसे कई निजी स्कूल हैं जो हर साल फीस में बढ़ोतरी करते हैं गरीब किसान के बच्चे जो कभी बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़ते थे वो अब वहां से नाम कटवाकर सरकारी स्कूल में दाखिला करवा रहे हैं। ड्रेस, कॉपी, किताब, एडमिशन के नाम पर प्राइवेट स्कूल मोटी रकम वसूल रहे हैं जबकि सरकारी स्कूलों में 2000 में उनका बच्चा पूरा साल भर पढ़ लेता है। ड्रेस तक पहन लेता है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था पर लगाम नहीं है। ये तय होना चाहिए कि इस स्कूल को क्या चाहिए कि इस स्कूल को चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार झा ने बताया कि फीस संबंधी हमारा फी अधिनियम है। 2020 एनपी के तहत उसके तहत हम लोगों ने जिला स्तरीय कमेटी गठित किया हुआ है। सारे विद्यालयों में भी ये कमेटीयां गठित हैं और जिन विद्यालयों में गठित भी है उसको रिन्यू भी कराया जा रहा है। उस पर काम भी हो रहा है। कुछ 12 विषय हैं जिस पर विद्यालय फी ले सकते हैं। अधिनियम के तहत वो विद्यालयों को सूचित किया हुआ है और वो न्यूनतम अधिकतम ऐसा कुछ नहीं है। जिला शिक्षाधिकारी की माने तो जिला स्तरीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में कमेटी गठित है। उसमें प्रोविजन ये है कि यदि 8व से ज्यादा की वृद्धि यदि कोई विद्यालय कर रहा है एनुअल फी में तो वो फिर जिला के पास आता है अनुमोदन के लिए और यदि 8% से कम है तो वो विद्यालय स्तरीय समिति होती है जिसमें हमारे नोडल अधिकारी भी होते हैं जो नोडल प्राचार्य होते हैं और पालक गरी भी होते हैं, विद्यालय समिति होती है वो मिलके उसका निर्धारण करते हैं। दिनेश कुमार झा ने बताया कि इस विषय पर अभी हमने वेबसाइट स्टार्ट किया है जिले में जो कि नवाचार के तहत है और वो ओपन है।

छत्तीसगढ़	प्रमुख समाचार	मनेंद्रगढ़ में पीलिया का प्रकोप, दूषित पानी से बीमार हो रहे बच्चे	महिला आरक्षण बिल लोकसभा में विफल, सरोज पांडेय का धरना	79 लाख गबन करने वाला कियोस्क संचालक गिरफ्तार	मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी प्यासा है गांव	अवैध खनन पर प्रशासन सख्त, 70 ट्रेक्टर हाइवा जब्त
		मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेंद्रगढ़ में पीलिया (जॉन्डिस) के बढ़ते मामलों ने अब गंभीर रूप ले लिया है। लगभग 35 हजार की आबादी वाले इस शहर में दूषित पानी की सप्लाई लोगों की सेहत के साथ खुला खिलवाड़ कर रही है। हालात इतने खराब हैं कि बीते तीन महीनों में करीब 40 पीलिया के मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि सिर्फ 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच ही 19 नए मरीज अस्पताल पहुंचे हैं। इनमें से 8 मरीज अभी भी भर्ती हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन मरीजों में बड़ी संख्या मामूम बच्चों की है। विशेषज्ञों के अनुसार, दूषित पानी और अस्वच्छ खानपान पीलिया फैलने के प्रमुख कारण हैं। लेकिन शहर में इन दोनों पर ही नियंत्रण नहीं दिख रहा। शहर में नगर पालिका द्वारा सप्लाई किया जा रहा पानी अब लोगों के लिए खतरा बन चुका है। आरोप है कि पानी को ठीक से फिल्टर नहीं किया जा रहा, जिससे गंदा पानी सीधे घरों तक पहुंच रहा है और पीलिया का प्रकोप बढ़ रहा है। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं।	महिला आरक्षण बिल लोकसभा में विफल, सरोज पांडेय का धरना दुर्ग। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के विरोध में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय गांधी पुतला के सामने धरने पर बैठ गईं। इस दौरान उनके साथ भाजपा की सैकड़ों महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार के समर्थन में आवाज बुलंद की धरने को संबोधित करते हुए सरोज पांडेय ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां राजनीतिक स्वार्थ के कारण एकजुट होकर इस महत्वपूर्ण बिल का विरोध कर रही हैं। उनका आरोप था कि विपक्ष को डर है कि इस बिल का लाभ भाजपा और पीएम को मिलेगा, इसलिए उन्होंने वोटिंग के समय सदन से दूरी बनाई। पांडेय ने कहा कि देश की महिलाओं को इस बिल से 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने की उम्मीद थी, जिससे उन्हें विस व संसद में अधिक भागीदारी मिलती। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी स्वयं महिला होते हुए भी इस मुद्दे पर गंभीर नहीं दिखीं।	79 लाख गबन करने वाला कियोस्क संचालक गिरफ्तार कोरबा। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर ने 16 अप्रैल को रूमगरा निवासी एक कियोस्क संचालक गौरव शुक्ला (47 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। जिस पर भीपीएल वर्ग के पीएम आवास के हितग्राहियों के पैसों को गबन करने का आरोप है। आरोपी चालाकी से कम जागरूक ग्रामीणों के इंदिरा आवास (अब पीएम आवास) की राशि को अपने खाते में हस्तांतरित करवा लेता था। एक-एक कर उसने 79 लाख रुपए गबन किए हैं। ईओडब्ल्यू से मिली जानकारी के अनुसार गरीबों के आवास के लिए शासन से मिलने वाली इंदिरा आवास योजना की राशि कोरबा जिले के विभिन्न ग्रामों के लिए किशतों में आई थी। उसी राशि को वर्ष 2017 में अपने खाते में स्थानांतरित कर गबन किया गया है। कोरबा के दुर्गम ग्रामीण अंचलों के भोले-भाले लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करते हुए उसका नाजायज फायदा उठाकर उा ने उनके हक के 79 लाख रुपये का गबन किया था। काफी छानबीन और 9 साल बाद ईओडब्ल्यू-एसबी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।	मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी प्यासा है गांव गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जल जीवन मिशन के दावों की पोल गौरेला विकासखंड की ग्राम पंचायत चुकतीपानी में खुलती नजर आ रही है। जहां एक ओर सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने बड़ी-बड़ी बातें करती है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा आदिवासी समाज आज भी बूढ़-बूढ़ पानी के लिए मीलों का सफर तय करने को मजबूर हैं। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते वर्ष मई 2025 में मुख्यमंत्री गुप्ता देव साय की जन चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने सीधे उनसे पानी की समस्या की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद इंजीनियर को कड़ी फटकार लगाते हुए जल्द समाधान के निर्देश दिए थे। लेकिन विडंबना है कि साल भर बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। चुकतीपानी का बाजारडाड़ क्षेत्र, जो मैकल पर्वत की तराई में बसा है, अपनी जटिल भौगोलिक स्थिति के कारण कम भूजल स्तर की समस्या से जूझ रहा है। स्थानीय के अनुसार संबंधित विभाग भौगोलिक स्थिति को नजरअंदाज कर रहा है।	अवैध खनन पर प्रशासन सख्त, 70 ट्रेक्टर हाइवा जब्त बिलासपुर। जिले में अवैध बोर खनन और रेत उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तुरकाडीह गांव में अवैध बोर मशीन जब्त की गई, वहीं निरतु घाट पर 70 ट्रेक्टर अवैध रेत, एक एक्सबीटर, तीन हाइवा और तीन ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। तुरकाडीह में अवैध बोर खनन की सूचना पर सकरी तहसीलदार, थाना प्रभारी, हल्का पटवारी और कोनी थाना की संयुक्त टीम ने जांच की। जांच में पाया गया कि बोर खनन के लिए वैध अनुमति नहीं ली गई थी। कलेक्टर के 6 अप्रैल को जारी बोर खनन पर प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर बोर मशीन को जब्त कर कोनी थाना को सौंपा। जिले में 6 अप्रैल से बोर खनन पर प्रतिबंध लगाया है। प्रशासन इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित करा रहा है और अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रख रहा है। अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ जिले में एक और बड़ी कार्रवाई की गई। तखतपुर एसडीएम के मार्गदर्शन में एक संयुक्त टीम ने मौके पर अवैध रूप से रेत उत्खनन व परिवहन पर जेसीबी, हाइवा पकड़ा।

बाइक सवार को बचाने घर में घुसी वाहन, एसडीएम और पुलिसकर्मी हुए घायल

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में आज एसडीएम की कार दुर्घटना का शिकार हो गई। बाइक सवार को बचाने उनकी सरकारी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे घर में जा घुसी।



हादसे में रामानुजगर एडीएम अजय मांडियम सहित दो आरक्षक और वहां चालक घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक, एसडीएम अजय मांडियम रामानुजगर से सूरजपुर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान देवनगर गांव में सामने से आ रहे एक बाइक सवार को बचाने के लिए एडीएम की कार अनियंत्रित हो गई और वाहन एक

मकान में जा घुसी। गनीमत रही कि उस वक्त घर पर कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस दुर्घटना में एसडीएम सहित अन्य लोगो को मामूली चोटें आई है। हादसे की सूचना पर कलेक्टर मौके पर पहुंचे और अपनी वाहन से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में जारी है।

14 साल बाद गांव लौटा डीआरजी जवान, कभी नक्सलियों के डर से छोड़ दिया था गांव

नारायणपुर। डीआरजी जवान बुधराम वर्धा की आंखों में आज खुशी के आंसू हैं। पूरे 14 साल बाद वह अपने गांव वापस लौटे हैं और दोस्त रिश्तेदार से मिलकर बेहद खुश हैं। दरअसल ये उस युवक की कहानी है, जिसे कभी अपने ही गांव से जान बचाकर भागना पड़ा था, लेकिन आज वह सुरक्षा बल का हिस्सा बनकर अपने गांव आलबेड़ा लौटा है।



आलबेड़ा गांव नारायणपुर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर है। यहां कभी नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती थी। यहां की भौगोलिक दुर्गमता, घने जंगल और सीमित प्रशासनिक पहुंच ने नक्सलियों को पनपने का अवसर दिया। ग्रामीणों के लिए जीवन किसी संघर्ष से कम

नहीं था। हर दिन अनिश्चितता से भरा होता था और हर रात भय की चादर ओढ़कर गुजरती थी। इसी भयावह दौर के बीच बुधराम वर्धा का जीवन भी एक बड़ा मोड़ लेता है। बुधराम वर्धा बताते हैं, साल 2011-12 के आसपास का वह समय, जब नक्सलियों का प्रभाव अपने चरम पर था। गांव में कुछ लोगों को

नक्सलियों ने प्रताड़ित कर मौत के घाट उतार दिया। यह पूरे गांव के लिए एक खौफनाक संदेश था, जो विरोध करेगा, उसका यही अंशाम होगा। बुधराम बताते हैं कि उस समय उनकी उम्र महज 25 वर्ष थी। जीवन के उस पड़ाव पर, जहां सपने आकार लेते हैं, उन्हें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ी। नक्सलियों की धमकियां लगातार उनके परिवार तक पहुंच रही थीं। हर दिन यह डर बना रहता था, कि अगला निशाना उनका परिवार हो सकता है। आखिरकार वह दिन आया, जब बुधराम ने अपने पुत्रैनी घर, जमीन और बचपन की यादों को पीछे छोड़ने का कठिन फैसला लिया। पूरे परिवार के साथ उन्हें गांव से नक्सलियों के फरमान की वजह से बेदखल होना पड़ा।

परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा आज

जगदलपुर। जगदलपुर में 19 अप्रैल को परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 21 केंद्रों पर 5720 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रशासन ने समय, सुरक्षा जांच, प्रवेश पत्र और ड्रेस कोड को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि परीक्षा सही तरीके से संपन्न हो सके। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने परिवहन विभाग के रिक्त पदों के लिए यह लिखित परीक्षा आयोजित की है।

परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक तय किया गया है। बस्तर जिले में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां अलग-अलग संख्या में परीक्षार्थियों को बिठाया जाएगा। प्रमुख केंद्रों में काकतीय पीजी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज,

दंतेश्वरी पीजी महिला महाविद्यालय और महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल शामिल हैं। प्रशासन के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 2 घंटे पहले केंद्र पहुंचना अनिवार्य है। सुबह 10:30 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सुरक्षा के लिए सभी केंद्रों में मेटल डिटेक्टर से जांच की जाएगी। बिना वैध प्रवेश पत्र और पहचान पत्र के प्रवेश नहीं मिलेगा। पहचान के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड जरूरी रहेगा। प्रवेश पत्र पर फोटो साफ नहीं होने पर दो पासपोर्ट फोटो साथ लाना होगा। ड्रेस कोड के कपड़े और चप्पल पहनना अनिवार्य किया गया है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 5 अतिरिक्त न्यायाधीश बने स्थायी न्यायाधीश

रायपुर। भारत के राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरांत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पांच

अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। नियुक्त किए गए न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत, न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल, न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल, न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु तथा न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद शामिल हैं। इन सभी न्यायाधीशों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्तियां न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ मामलों के त्वरित निपटारे में सहायक होंगी।

पूज्य सिविल लाइन्स सिंधी पंचायत के संजय जैरिंघ अध्यक्ष निर्वाचित

रायपुर। पूज्य सिविल लाईंस सिंधी पंचायत की नवीन कार्यकारिणी (2026-28) का गठन सर्वसम्मति से किया गया है। पंचायत के अध्यक्ष के रूप में श्री संजय जैरिंघ तथा महासचिव के रूप में श्री मोहन वर्ल्यानी का चयन किया गया है। पंचायत के संरक्षक मंडल में श्री गोपीचंद खत्री, श्री कन्हैयालाल छुगानी, श्री अमर गिदवानी, श्री कमल लहेजा एवं श्री राजकुमार कोडवानी शामिल हैं। वहीं विशेष वरिष्ठ मार्गदर्शकों के रूप में श्री आसुदाराम वाधवानी, श्री दुलाराम वाधवा, श्री कन्हैयालाल अटलानी एवं श्री ताराचंद मंधान को दायित्व सौंपा गया है। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के रूप में श्री नंदलाल जसवानी, श्री प्रकाश जादवानी, श्री हीरानंद दुल्हानी, श्री मुरली कोडवानी एवं श्री संजय आहूजा को शामिल किया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में श्री जीवतराम बजाज एवं श्री संजय जादवानी को जिम्मेदारी दी गई है। सचिव पद पर श्री जय आर्य एवं श्री अशोक निहलानी, कोषाध्यक्ष के रूप में श्री दीपक खेमानाी तथा सह-कोषाध्यक्ष के रूप में श्री शैलेंद्र नैनानी एवं श्री सुशील दरौरा को नियुक्त किया गया है।

समीर विश्नोई व पत्नी की करोड़ों की संपत्ति एसीबी/ईओडब्ल्यू ने किया अटैच

रायपुर। निर्लंबित आईएएस समीर विश्नोई और उसकी पत्नी प्रीति विश्नोई की करोड़ो रूपये कीमत की संपत्तियों को एसीबी ईओडब्ल्यू ने अटैच कर दिया है। एसीबी/ईओडब्ल्यू ने पिछले दिनों सभी संपत्तियो को सीज करने का ब्योरा विशेष न्यायाधीश के सामने अनुमति के लिए लगाया था जिसे कोर्ट के आदेश मिलने के बाद ये करोड़ों की संपत्तियां जब्त कर ली है। इससे पहले निर्लंबित रानू साहू, सौम्या चौरसिया की भी संपत्ति अटैच की जा चुकी हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब्त संपत्तियां समीर विश्नोई और उनकी पत्नी प्रीति विश्नोई के नाम करीब 15 से 20 करोड़ रुपयों की बेनाम संपत्तियां अटैच की गई है। सरकारी अधिकारी होने के कारण एसीबी/ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करने के बाद जांच में खुलासा हुआ है कि जब्त संपत्तियां समीर विश्नोई व पत्नी प्रीति विश्नोई के नाम 3 से 4 फर्म बनाकर अवैध राशि से खरीदी गई थी। इनमें महासमुंद्र में 22 एकड़ जमीन, नया रायपुर स्थित बेशकीमती जमीन, गायत्री नगर स्थित मकान समेत कई बेनामी संपत्तियां सीज कर ली गई है। जांच में सामने आया कि ज्यादातर संपत्तियां रिस्तेदारों और पत्नी के नाम अवैध निवेश से खरीदी गई थी जिन्हें जब्त किया गया है।

सुषमा जेठानी होंगी छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी की अध्यक्ष

रायपुर। भिलाई-3 के वार्ड नंबर 16 के बाजार चौक निवासी श्रीमती सुषमा जेठानी को राज्य सरकार ने अस्थाई रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश पर्यंत छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। लंबे समय समाज की ओर से अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की जा रही थी और आज राज्य सरकार ने सुषमा जेठानी को छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी की अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। उनकी नियुक्ति से समाज में हर्ष व्याप्त है और इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है।

छत्तीसगढ़ में हर जिले में बनेंगे एनीमल बर्थ कंट्रोल सेंटर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आवारा श्वाओं की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पशुधन विकास मंत्री रामविचार नेताम ने घोषणा की है कि प्रदेश के सभी 33 जिलों में एनीमल बर्थ कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से श्वाओं की नसबंदी और टीकाकरण अभियान चलाकर उनकी संख्या नियंत्रित करने के साथ ही रैबीज जैसी बीमारियों की रोकथाम की जाएगी। मंत्रालय महानदी क्षेत्र में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि नगरीय निकायों के सहयोग से इन केंद्रों का संचालन किया जाएगा, ताकि शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण हो सके। बैठक में मंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जानकारी देते हुए कहा कि अब सभी महिला हितग्राहियों को दुधारू गाय उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक बना कानून, राजपत्र में हुआ प्रकाशित

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जबरन और प्रलोभन से धर्मांतरण पर रोक लगाने 19 मार्च को विधानसभा में पारित छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक ने कानून का रूप ले लिया है। विधेयक पर 6 अप्रैल को राज्यपाल रमेन डेका के हस्ताक्षर करने के बाद अब छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में 19 मार्च को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 को विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श के बाद पारित किया गया था। विधेयक का उद्देश्य राज्य में धर्मांतरण से संबंधित गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करना है।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने विधेयक के संबंध में कहा था कि वर्ष 1968 से लागू प्रावधान वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप पर्याप्त नहीं रह गए थे। बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में

धर्मांतरण से जुड़े विवादों के कारण सामाजिक तनाव और वर्ग संघर्ष की स्थितियां बनीं, जो कई बार प्रशासन और न्यायालय तक पहुंचीं। ऐसे परिदृश्य में एक स्पष्ट, पारदर्शी और प्रभावी कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई, जिससे समाज में बार-बार उत्पन्न होने वाले विवादों को रोका जा सके और समरसता को बनाए रखा जा सके।

विधेयक में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। अब धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन देना होगा, जिसके बाद निर्धारित समय-सीमा में सूचना सार्वजनिक की जाएगी और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। जांच के उपरांत ही प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता रहे, लेकिन यह परिवर्तन किसी दबाव, प्रलोभन या भय के

दिशा दर्शन भ्रमण आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम : लक्ष्मी राजवाड़े

51 महिलाओं को मिला लघु उद्योग का व्यावहारिक ज्ञान

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की पहल और मार्गदर्शन में संचालित दिशा दर्शन भ्रमण योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में प्रभावी रूप से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में सूरजपुर जिले की लगभग 51 महिलाएं, जो विभिन्न महिला स्व सहायता समूहों से जुड़ी हैं, अध्ययन भ्रमण के तहत रायपुर पहुंचीं।

भ्रमण के दौरान महिलाओं ने रायपुर-खरोरा स्थित सोया प्रोसेसिंग प्लांट का अंदरलोकन कर उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं विपणन की प्रक्रियाओं को विस्तार से समझा। प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाओं में स्वरोजगार के प्रति नया आत्मविश्वास जागृत हुआ और उन्होंने अपने क्षेत्रों में छोटे स्तर पर प्लांट स्थापित कर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की।

इस अवसर पर मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े स्वयं प्लांट परिसर में उपस्थित रहीं और महिलाओं से सीधे संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इस प्रकार के भ्रमण कार्यक्रम उन्हें व्यवहारिक अनुभव प्रदान करते हैं, जो उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि इच्छुक महिला स्व सहायता समूहों को सोया प्रोसेसिंग जैसे लघु उद्योग स्थापित करने हेतु हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को योजनाओं से जोड़ते हुए उन्हें वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं, बल्कि समाज में नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही हैं।मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि दिशा दर्शन भ्रमण योजना के माध्यम से राज्य सरकार महिलाओं को ज्ञान, कौशल और अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर सशक्त रूप से अग्रसर कर रही है।

महिला सशक्तीकरण के लिए टाउन-हॉल बैठकें

■ नारी शक्ति वंदन सम्मेलन और रोड-शो होंगे आयोजित

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने महिला सशक्तीकरण के लिए टाउन-हॉल बैठकों, नारी शक्ति वंदन सम्मेलनों और रोड-शोज के आयोजन एवं आवश्यक समन्वय के लिए राज्य के सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने मंत्रालय से सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जारी परिपत्र में कहा है कि महिलाओं के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तीकरण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य शासन द्वारा एक विशेष अल्पकालिक एवं गहन जन-जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टरों के

संबंधित जन-जागरूकता अभियान के प्रथम चरण में संबंधित निकायों को विशेष सामान्य सभा आहूत कर कार्यक्रम की महत्ता पर विशेष चर्चा एवं संकल्प पारित करने को कहा गया है। राज्य शासन की प्रमुख प्लैंगशिप योजनाओं को आमजनों तक पहुंचाने एवं इसके लिए जागरूक करने महिला हितग्राहियों, स्वसहायता समूहों और स्थानीय जमीनी नेटवर्क को सक्रिय कर हितग्राहियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने विभागीय अभिसरण के जरिए जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में विभिन्न योजनाओं के लाभ की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने सभी विभागों से आवश्यक समन्वय स्थापित कर स्टॉल व अन्य उपाय करने के निर्देश निकायों को दिए हैं।

भारत को कबड्डी विश्वकप और एशियन चैंपियन बनाने वाली संजू देवी को 50 लाख की प्रोत्साहन राशि

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सौंपा चेक, राज्य में पहली बार किसी खिलाड़ी को दी गई है इतनी बड़ी प्रोत्साहन राशि

रायपुर। भारत को कबड्डी विश्वकप और एशियन चैंपियनशिप दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली संजू देवी को राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी खिलाड़ी को इतनी बड़ी प्रोत्साहन राशि दी गई है। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने आज नवा रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित सम्पन्न समारोह में उन्हें यह राशि सौंपी। श्री साव ने इस दौरान बिलासपुर के चिंवारजपारा कबड्डी क्लब को कबड्डी मैट भी प्रदान किया।

संजू देवी को उनके शानदार खेल की वजह से पिछले साल नवम्बर में बांग्लादेश में आयोजित कबड्डी विश्वकप मंर मोस्ट वेल्युबल प्लेयर चुना गया था। कबड्डी विश्वकप के फाइनल में भारत को मिले 35 प्वाइंट्स में से 16 प्वाइंट्स अकेले संजू ने दिलाए थे। सेमी-फाइनल सहित अन्य मैचों में भी उन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

संजू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य की पहली कबड्डी खिलाड़ी है। कबड्डी विश्व कप के साथ ही उन्होंने पिछले साल मार्च में ईरान में आयोजित एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था और भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। कोरबा के छोटे से गांव केराकछार की श्रमिक दंपति की संतान 23 साल की संजू राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित बिलासपुर के बहतराई आवासीय बालिका कबड्डी अकादमी में जुलाई-2023 से प्रशिक्षण ले रही है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने संजू देवी को सम्मानित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में राज्य में लगातार खेल और खिलाड़ियों की तरक्की व बेहतरी के लिए काम हो रहे हैं। संजू

में भी उन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

संजू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य की पहली कबड्डी खिलाड़ी है। कबड्डी विश्व कप के साथ ही उन्होंने पिछले साल मार्च में ईरान में आयोजित एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था और भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। कोरबा के छोटे से गांव केराकछार की श्रमिक दंपति की संतान 23 साल की संजू राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित बिलासपुर के बहतराई आवासीय बालिका कबड्डी अकादमी में जुलाई-2023 से प्रशिक्षण ले रही है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने संजू देवी को सम्मानित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में राज्य में लगातार खेल और खिलाड़ियों की तरक्की व बेहतरी के लिए काम हो रहे हैं। संजू



कारण न हो, इसकी जांच अनिवार्य होगी।

इस कानून में धर्मांतरण कराने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए पंजीयन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी को हर वर्ष विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें धर्मांतरण से संबंधित जानकारी का विवरण शामिल होगा। ग्राम सभा को भी इस प्रक्रिया में भागीदारी दी गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। विवाह को

वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बचाव में उतरे भाजपा सांसद जिंदल

रायपुर। वेदांता पावर प्लांट में 14 अप्रैल को हुए हादसे में वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बचाव में भाजपा सांसद और बड़े उद्योगपति नवीन जिंदल सामने आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया में अपने पोस्ट के जरिए पावर प्लांट हादसे में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होने के बाद भी अनिल अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर सवाल उठाया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से चुने गए भाजपा सांसद और जिंदल स्टील के चेयरमैन नवीन जिंदल ने इंट्राग्राम में किए अपने पोस्ट में लिखा है कि छत्तीसगढ़ की यह रासदी बेहद पीड़ादायक है। 20 परिवारों ने सब कुछ खो दिया है। प्रभावित परिवारों के लिए उचित मुआवजा, आजीविका का समर्थन और पूरी तरह से निष्पक्ष जांच अनिवार्य है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि किसी भी जांच से पहले अनिल अग्रवाल का नाम एफआईआर में शामिल करना गंभीर सवाल खड़े करता है। वे एक साधारण और पिछड़े वर्ग के परिवार से उठकर अपने दम पर एक वैश्विक उद्योग खड़ा करने वाले व्यक्ति हैं। उस प्लांट के संचालन में उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। उन्होंने तर्क दिया कि जब पीएसयू प्लांट्स या रेलवे में हादसे होते हैं, तो क्या हम चेयरमैन का नाम लेते हैं? नहीं लेते। यही मानक निजी क्षेत्र पर भी लागू होना चाहिए। पहले जांच हो। सबूतों के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाए।

धर्मांतरण का आधार नहीं माना गया है, और विवाह के बाद भी धर्म परिवर्तन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होगा।

अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए विधेयक में कड़े दंड के प्रावधान किए गए हैं। जिसमें अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए सामान्य अवैध धर्मांतरण पर 7 से 10 वर्ष तक कारावास एवं न्यूनतम 5 लाख रुपए तक जुर्माना, विशेष वर्ग जिसमें महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, नाबालिग आदि शामिल हैं, के अवैध धर्मांतरण पर 10 से 20 वर्ष तक कारावास एवं न्यूनतम 10 लाख रुपए जुर्माना, सामूहिक अवैध धर्मांतरण पर 10 वर्ष से आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 25 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है।

इसी तरह लोक सेवक द्वारा इस प्रकार का अपराध किया जाता है तो उसे 10 से 20 वर्ष कारावास एवं 10 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है। वैसे ही धन के माध्यम से धर्मांतरण किए जाने

रायपुर में पानी के लिए तरस रहे लोग कांग्रेसियों के साथ नगरवासियों ने घेरा जोन कार्यालय

रायपुर। राजधानी रायपुर में पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस नेताओं और स्थानीय लोगों ने शनिवार को जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमटी के अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में नगरवासियों शामिल हुए। कापा, नहरपार, डबरीपार, गणेशनगर और चंडीनगर जैसे इलाकों में पिछले एक महीने से पानी की आपूर्ति ठप होने से लोगों में भारी नाराजगी दिखाी।

लोगों ने बताया कि नगर निगम की ओर से नियमित रूप से टैंकर नहीं भेजे जा रहे हैं, जिससे हालात और खराब हो गए हैं। खासकर महिलाओं ने अपनी परेशानी साझा करते हुए कहा कि उन्हें पिछले एक महीने से दूसरे घरों से पानी लाना पड़ रहा है। कई बार तो पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाए और पाइपलाइन के जरिए नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने कहा कि नगर निगम जोन क्रमांक 9 में बीते एक महीने से पाइपलाइन से पानी नहीं आ रहा है। लोगों को राहत देने के लिए टैंकर भेजे जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ चार टैंकर पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मांग की है कि कम से कम 10 टैंकरों की व्यवस्था की जाए, ताकि पानी की आपूर्ति

संबंधित व्यक्ति को 10 से 20 वर्ष कारावास एवं 20 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है। भय या प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण पर 10 से 20 वर्ष कारावास एवं न्यूनतम 30 लाख रुपए जुर्माना का भी प्रावधान है। इन अपराधों की पुनरावृत्ति किए जाने पर संबंधित को आजीवन कारावास और पीड़ितों के लिए प्रतिकार व्यवस्था विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है।

इस विधेयक में प्रतिकार व्यवस्था के तहत यदि किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन दबाव, प्रलोभन या धोखे से किया गया हो, तो उसे स्पष्ट रूप से पीड़ित माना जाएगा। ऐसे मामलों में न्यायालय आरोपी को पीड़ित को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दे सकता है। इसका भी प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के तहत मामलों की जांच उप निरीक्षक या उससे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाएगी। ऐसे मामलों में प्रमाण का भार आरोपी पर होगा। मामलों की सुनवाई के लिए निर्धारित न्यायालयों को अधिसूचित किया जाएगा।



सुचारु हो सके। हमने पाइप लाइन के जरिए भी पानी की आपूर्ति हो, इसकी मांग की है। निगम को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर पानी की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए ना की गई तो फिर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।

कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने भी नगर निगम पर निशाना साधते हुए कहा कि रायपुर के अधिकांश वार्ड पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसी के विरोध में आज जोन क्रमांक 9 कार्यालय का घेराव किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तीन दिन के भीतर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। जोन कमिश्नर राकेश शर्मा ने कहा कि लोगों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए टैंकरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। जिन वार्डों में पानी की किल्लत है वहां अतिरिक्त टैंकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

करोड़ों के घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई, नगर निगम के 4 अधिकारी निर्लंबित

रायपुर। नगर निगम में 100 करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आयुक्त ने चार अधिकारियों को निर्लंबित कर दिया है। नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने बताया कि चार सदस्यीय जांच कमटी की रिपोर्ट के आधार पर जोन क्रमांक 10 के तत्कालीन जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे, कार्यपालन अभियंता आशीष शुक्ला, इंजीनियर योगेश यादव और अजय श्रीवास्तव के खिलाफ निर्लंबन की कार्रवाई की गई है। मामले में विभागीय जांच भी की जाएगी। साथ ही विधिक कार्रवाई के साथ-साथ वेतन वृद्धि में भी रोक लगाई जाएगी।



बताया जा रहा है कि यह

मामला करीब 150 से 159 एकड़ अवैध जमीन को गलत तरीके से वैध बनाने की साजिश से जुड़ा हुआ है। जांच में सामने आया है कि पूरी प्रक्रिया में नगर निगम मुख्यालय को बायपास किया गया और संरचना अनुमोदन व टीएमसी अप्रुवल में गंभीर अनियमितताएं बरती गईं।

इस मामले की जांच के लिए गठित चार सदस्यीय कमटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके आधार पर निर्लंबन की कार्रवाई की गई। जांच समिति में पंकज शर्मा (अपर आयुक्त, नगर निवेश) को अध्यक्ष बनाया

गया था, जबकि आभाष मिश्रा, आशुतोष सिंह और सोहन गुप्ता सदस्य के रूप में शामिल थे। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि जांच के दौरान कई बार मूल नस्ती (दस्तावेज) मांगे जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराए गए। साथ ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका भी जताई गई है।

संघों के माध्यम से हों। खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बजट में पर्याप्त प्रावधान किए हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती तनुजा सलाम, छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के अध्यक्ष श्री शशिकांत बघेल और संजू देवी के कोच श्री दिल कुमार राठौर सहित राज्य शासन के विभिन्न अकादमियों में प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ी, कबड्डी संघ के पदाधिकारी एवं अच्छा खेलने का प्रोत्साहन मिले, इसके लिए सरकार

संजू देवी को 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने अभी हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की शानदार मेजबानी की है। बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक के भी वृहद आयोजन किए गए हैं। श्री साव ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में लगातार खेल प्रतियोगिताएं चलती रहें, चाहे वो सरकार के माध्यम से हों, अन्य संस्थाओं के माध्यम से हों या खेल

संघों के माध्यम से हों। खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बजट में पर्याप्त प्रावधान किए हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती तनुजा सलाम, छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के अध्यक्ष श्री शशिकांत बघेल और संजू देवी के कोच श्री दिल कुमार राठौर सहित राज्य शासन के विभिन्न अकादमियों में प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ी, कबड्डी संघ के पदाधिकारी एवं अच्छा खेलने का प्रोत्साहन

मिले, इसके लिए सरकार

संघों के माध्यम से हों। खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बजट में पर्याप्त प्रावधान किए हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती तनुजा सलाम, छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के अध्यक्ष श्री शशिकांत बघेल और संजू देवी के कोच श्री दिल कुमार राठौर सहित राज्य शासन के विभिन्न अकादमियों में प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ी, कबड्डी संघ के पदाधिकारी एवं अच्छा खेलने का प्रोत्साहन

मिले, इसके लिए सरकार

12 साल में पहली बार मोदी के विधेयक की संसद में हार

नीरज कुमार दुबे

लोकसभा में शुक्रवार को घटा घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मोड़ के रूप में दर्ज किया जाएगा। मोदी सरकार द्वारा लाया गया संविधान संशोधन विधेयक, जो परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों को जोड़ता था, अंततः लोक सभा में गिर गया। यह सिर्फ एक सामान्य विधायी हार नहीं, बल्कि एक मील का पत्थर इसलिए भी है क्योंकि वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के किसी विधेयक को पहली बार संसद में वोटिंग के दौरान पराजय का सामना करना पड़ा है। इससे पहले भूमि अधिग्रहण कानून और कृषि कानूनों जैसे मुद्दों पर सरकार को चुनौतियां जरूर मिली थीं, लेकिन वह परिस्थितियां अलग थीं और इस तरह सीधे सदन में वोट के जरिए पराजय नहीं हुई थी। हम आपको बता दें कि वोटिंग से पहले ही माहौल गरम हो चुका था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ नेताओं के बीच पर्दे के पीछे गहन बातचीत चल रही थी। शीर्ष नेताओं की लगातार बैठकें हो रही थीं और सदन के भीतर जोरदार विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण को लेकर सत्ता पक्ष की तीखी प्रतिक्रिया ने माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया। हालांकि शाम को जब केंवली गृह मंत्री अमित शाह बोलने के लिए खड़े हुए, तब तक यह लगभग स्पष्ट हो चुका था कि विधेयक का क्या हथ्र होने वाला है, लेकिन सरकार इसे वोटिंग तक ले जाने के लिए दृढ़ नजर आई। संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 की यह हार मोदी सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक असहजता के रूप में देखी जा रही है। साथ ही यह घटना न केवल एकजुट विपक्ष की ताकत का संकेत देती है, बल्कि संविधान जैसे गंभीर विषयों पर व्यापक और गंभीर संवाद की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। इस पराजय ने यह भी स्पष्ट किया कि संसद में केवल संख्याबल ही नहीं, बल्कि राजनीतिक सहमति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। हम आपको बता दें कि विधेयक को प्रस्तुति और उसकी संरचना ने भी कई सवाल खड़े किए। सबसे अधिक विवाद इस बात को लेकर हुआ कि महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे दो अलग विषयों को एक साथ क्यों जोड़ा गया। विपक्ष ने इसे एक रणनीतिक चाल बताया, जिसका उद्देश्य एक मुद्दे की आड़ में दूसरे को आगे बढ़ाना था। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कदम पारदर्शिता के विपरीत है। वहीं सरकार के भीतर भी इस विधेयक को लेकर अलग अलग आकलन सामने आए। हालांकि सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी घटक इस मुद्दे पर एकजुट रहे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का मानना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह विधेयक इसलिए लाये क्योंकि इससे महिला मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ और मजबूत हो सकती थी। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के बीच भाजपा के समर्थन में वृद्धि देखी गई है और यह विधेयक उस समर्थन को और मजबूत करने का एक प्रयास माना गया। हालांकि विधेयक पारित नहीं हो सका, लेकिन इसने यह जरूर स्पष्ट कर दिया कि कौन दल महिला आरक्षण के पक्ष में हैं और कौन नहीं। बहरहाल, अब नजर इस बात पर टिकेगी कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा किस तरह राजनीतिक रंग लेता है और भाजपा इसे चुनाव प्रचार में किस रणनीति के साथ उठाती है। संकेत तो मिल ही चुके हैं कि पार्टी इस पर आक्रामक रुख अपनाने वाली है। आज विभिन्न समाचारपत्रों में जारी विश्लेषणों के माध्यम से भाजपा ने स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि वह महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में है।

पुराण दिग्दर्शन

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)
यास्क की सम्पति
यह वृत्रासुर कौन है ? – इस प्रश्न को लेकर वेदों के मर्मज्ञ श्री यास्काचार्य ने अपने प्रसिद्ध निरुक्त ग्रन्थ में इस प्रकार लिखा है–
तक्रो वृत्रः मेघ इति नैरुकाः।
त्वार्ष्टोऽसुर इत्यैतिहासिकाः।
अपां च ज्योतिषश्च मिश्रीभाव-कर्मणो वर्षकर्म जायते तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णना।

(निरुक्त 2।2)
अर्थात् (प्रश्न) [वेद में जिसका वर्णन श्राता है] वह वृत्र कौन है ?
(उत्तर) निरुक्त पक्ष वाले मेघ को वृत्र मानते हैं, और ऐतिहासिक लोग त्वष्टा के बेटे एक असुर को वृत्र कहते हैं। जलों और (वैद्युत) ज्योतिः के विमिश्रण से वृष्टि होती है, इसी को रूपकालङ्कार द्वारा इन्द्र और वृत्रासुर का युद्ध वर्णन किया जाता है।



रिलींजियस फ्रीडम फाउंडेशन यानी एमआरएफएफ है। एमआरएफएफ का कहना है कि उसे यूएस आर्मड फोर्सेस के अलग-अलग हिस्सों से 200 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। जिनमें मर्रींस, एयर फोर्स और स्पेस फोर्स के सदस्य भी शामिल हैं। इसमें यूएस मिलिट्री के एक नांत कमिश्ड ऑफिसर यानी एनसीओ के हवाले से बड़ा आरोप लगाया गया। एनसीओ ने अपनी शिकायत में बताया हमसे कहा गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को जीसस ने ईरान में सिग्नल फायर जलाने के लिए चुना है ताकि आर्मागडन हो और धरती पर उनकी यानी ईसा मसीह की वापसी हो। इसके अलावा जब धार्मिक प्रभाव को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से सवाल किया जाता है तो सोर्सिज और समर्थक जवाब देते हैं। जंग में तो हमेशा से ही धर्म और आस्था के जरिए फौजियों का हौसला बढ़ाया जाता रहा है। इसी तरह धार्मिक कट्टरपंथी के आरोप अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के आवाा यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्नेथ पर भी लगते रहे हैं। रिलींजियस एक्सट्रीमिज्म के स्कॉटर मैथ्यू डी टेलर ने इस बारे में कहा पीट हेगथ की लीडशिप में अमेरिकी जानबूझकर एक मुस्लिम मुल्क के खिलाफ जंग में जा रहा है। ये उसी तरह की सिचुएशन है

ज्ञान/मीमांसा

विपक्ष की दुविधा : आगे कुआं, पीछे खाई

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर भारत की संसद में चल रहा 16 से 18 अप्रैल 2026भारतीय संसद का विशेष सत्र केवल एक सामान्य विधायी प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक राजनीति के गहरे रणनीतिक, संवैधानिक और वैचारिक संघर्ष का प्रतीक बन गया।वर्तमान घटनाक्रम केवल एक घरेलू राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, संवैधानिक व्याख्याओं और राजनीतिक रणनीति का ऐसा संगम बन गया है, जिसपर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं।विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार द्वारा तीन महत्वपूर्ण विधेयकों महिला आरक्षण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम), परिसीमन (डेलिमिटेशन) और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े संशोधन को एक साथ पेश करना और फिर 16 अप्रैल 2026 को दैर रात्रि रूल 66 को निलंबित करने का कदम भारतीय संसदीय इतिहास में एक आधारपाण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।इसपर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया, संसदीय नियमों का प्रयोग और रूल 66 का निलंबन इन सभी ने इस पूरे घटनाक्रम को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया।यह घटनाक्रम केवल कानून बनाने की प्रक्रिया नहीं है,बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच रणनीतिक टकराव,राजनीतिक गणित, और संवैधानिक व्याख्याओं का एक जटिल खेल बन चुका है।।मैं यह मानता हूं कि सरकार ने जिन तीन विधेयकों को एक साथ पेश किया है, वे अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहला, नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण कानून), जो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान करता है।दूसरा, परिसीमन विधेयक, जो लोकसभा और विधानसभा सीटों के पुनर्विधारण से जुड़ा है। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित संशोधन विधेयक, जो प्रशासनिक और प्रतिनिधित्व संरचना को प्रभावित करता है। इन तीनों विधेयकों का एक साथ प्रस्तुत होना संयोग नहीं,बल्कि एक सुविचारित रणनीति प्रतीत होता है। सरकार का दावा है कि यह व्यापक सुधार का हिस्सा है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक पैकेजिंग कह रहा है।

साथियों बात अगर हम रूल 66 क्या है और क्यों बना विवाद का केंद्र ? इसकी समझने की करेंतो लोकसभा की कार्यप्रणाली में रूल 66 एक



तकनीकी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह नियम उन परिस्थितियों में लागू होता है, जब एक विधेयक दूसरे विधेयक पर निर्भर होता है। यदि आश्रित विधेयक पारित नहीं होता, तो मूल विधेयक भी निष्प्रभावी हो सकता है।सरकार ने इसी नियम को निलंबित करने का प्रस्ताव लाकर पूरे खेल की दिशा बदल दी।सामान्यतःप्रत्येक विधेयक पर अलग- अलग चर्चा और मतदान होता है, जिससे सांसद अपनी स्वतंत्र राय दे सकते हैं। लेकिन ‘रूल 66’ के निलंबन के बाद यह बाध्दता समाप्त हो जाती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब तीनों विधेयकों को एक साथ, एक ही प्रस्ताव के रूप में पारित कराया जा सकता।

साथियों बात अगर हम सरकार का मास्टरस्ट्रोक: संयुक्त मतदान की रणनीति को समझने की करें तो सरकार ने जिस रणनीति का उपयोग किया है,उसेराजनीतिक विश्लेषक मास्टरस्ट्रोक कह रहे हैं।। तीनों विधेयकों को एक ही प्रस्ताव में जोड़कर करने ने विपक्ष के लिए विकल्पों को सीमित कर दिया है।अब विपक्ष के सामने केवल दो ही रास्ते हैं,या तो तीनों विधेयकों के पक्ष में वोटकरें या तीनों के खिलाफ। यह रणनीति विपक्ष को एक धर्मसंकट में डालती है। यदि विपक्ष परिसीमन का विरोध करता है,तो उसे महिला आरक्षण के खिलाफ भी वोट देना पड़ेगा। और यदि वह महिला आरक्षण का समर्थन करता है, तो परिसीमन भी सटीक रूप से ही स्वतःपारित हो जाएगा।

साथियों बात अगर हम विपक्ष की दुविधा: आगे कुआं, पीछे खाई इसको समझने की करें तो, विपक्ष, विशेष रूप से इंडिया गठबंधन,इस स्थिति में फंस गया है जहां हर विकल्प राजनीतिक नुकसान की ओर ले जाता है। विपक्ष का रुख स्पष्ट है कि वह महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन परिसीमन को लेकर गंभीर आपत्तियां हैं, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में। विपक्ष का तर्क है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन

करने से दक्षिणभारत के राज्यों को नुकसान

होगा, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में सीटों का पुनर्वितरण उन्हें कम प्रतिनिधित्व की ओर ले जा सकता है। अब रूल 66 कैसिल करने से विपक्ष को तीनों विधेयकों को एक साथ मतदान करना पड़ेगा अगर वह यस में बदनाम करते हैं तो परिसीमन बिल भी पास होगा ना में मतदान करते हैं तो महिला

आरक्षण का अपने आप ही विरोध होगा।

साथियों बात अगर हम संख्या बल का गणित: सरकार के सामने चुनौती इसको समझने की करें तो, संविधान संशोधन विधेयकों को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई समर्थन। लोकसभा में कुल 540 सीटें हैं, जिनमें से 3 खाली हैं। ऐसे में 360 वोटों की जरूरत होती है। एनडीए के पास लगभग 293 सांसद हैं, जो आवश्यक संख्या से काफी कम है। इस स्थिति में सरकार को या तो विपक्ष के कुछ सांसदों का समर्थन चाहिए या फिर अनुपस्थित रहने वाले सांसदों की संख्या बढ़ानी होगी, ताकि आवश्यक बहुमत का आंकड़ा कम हो सके।

साथियों बात अगर हम अधिसूचना विवाद: कानून लागू या बचाने की कोशिश ? इसको समझने की करें तो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे विवादास्पद पहलू है 16 अप्रैल 2026 को जारी की गई अधिसूचना, जिसके तहत 2023 में पारित संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम को लागू करने की तारीख तय की गई। यह अधिसूचना ऐसे समय पर जारी की गई,जब संसद में उसी कानून में संशोधन पर बहस चल रही थी। विपक्ष ने इसे आधी रात का फैसला और हताशापूर्ण प्रयास करार दिया है। कांग्रेस नेता ने इस कदम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि कोई कानून संशोधन के अधीन है, तो उसे बिना नए विधायी समर्थन के लागू करना संवैधानिक रूप से संदिग्ध है। उन्होंने ‘रूल 66’ का हवाला देते हुए कहा कि यदि आश्रित विधेयक पारित नहीं होता, तो मूल कानून भी निष्प्रभावी हो सकता है। ऐसे में नियम को निलंबित कर अधिसूचना जारी करना कानून को बचाने का प्रयास प्रतीत होता है।

साथियों बात अगर हम टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का 17 अप्रैल 2026 को संसद में अपने विचारों के दौरान शाब्दिक हमला : चैरिटी

अनंत समृद्धि का दिन है अक्षय तृतीया

अधिक शादियां होती हैं। अक्षय तृतीया का पर्व बसंत और ग्रीष्म के संधिकाल का महोत्सव है। इस तिथि में गंगा स्नान, पितरों का तिल व जल से तर्पण और पिंडदान भी पूर्ण विश्वास से किया जाता है जिसका फल भी अक्षय होता है। इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। क्योंकि सतयुग की समाप्ति पर त्रेतायुग का आरंभ इसी तिथि से हुआ है।

माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया था। इसीलिए इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में मनाते हैं। मान्यता है कि आखा तीज के दिन राजा भागीरथ गंगा नदी को पृथ्वी पर लाये थे। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु तथा उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी



अपने गरीब मित्र सुदामा को दे दिया था। अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धेय ऋषि वेद व्यास ने महाभारत की रचना शुरू की थी। और पुराणों के अनुसार यह दिन त्रेता युग की शुरुआत का प्रतीक है। जो मानव जाति के चार युगों या युगों में से दूसरा है।

अक्षय तृतीया वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हिंदू शास्त्रों और पुराणों के अनुसार चार युग का चक्र होता है, जिसे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सतयुग जिसे इंसान के जीवन का सुनहरा

जी की पूजा की जाती है। आखा तीज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का जन्म भी हुआ था। यह वह दिन था जब भगवान कृष्ण ने अपनी सारी संपत्ति और सौभाग्य

अपने गरीब मित्र सुदामा को दे दिया था। अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धेय ऋषि वेद व्यास ने महाभारत की रचना शुरू की थी। और पुराणों के अनुसार यह दिन त्रेता युग की शुरुआत का प्रतीक है। जो मानव जाति के चार युगों या युगों में से दूसरा है। अक्षय तृतीया वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हिंदू शास्त्रों और पुराणों के अनुसार चार युग का चक्र होता है, जिसे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सतयुग जिसे इंसान के जीवन का सुनहरा

दौर कहा जाता है वो समाप्त हो जाता है और त्रेतायुग शुरू हो जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा जाता है। हिंदू परिवारों के लिए यह दिन बहुत ज्यादा महत्व रखता है।

अक्षय शब्द का अर्थ होता है कभी न मिटने या कम होने होने वाला। संस्कृत में अक्षय (अक्षय) शब्द का अर्थ समृद्धि, आशा, खुशी, सफलता होता है। ऐसे में तृतीया का अर्थ है चंद्रमा का तीसरा चरण। इसका नाम हिंदू कैलेंडर में वैसाख के वसंत महीने के तीसरे चंद्र दिवस के नाम पर रखा गया है। इस त्योहार को हम अपनी भाषा में आखातीज नाम से भी जानते हैं। जिसका अर्थ होता है जो कभी खत्म ना होने वाला। इसलिए माना जाता है की यह दिन हमारे लिए वस्तुओं की खरीदारी का सबसे शुभ दिन माना जाता है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है जो कभी खत्म न हो।

ईरान के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट से क्यों भिड़ गए पोप

अभिनय आकाश

ईरान के साथ जारी तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस जंग को एक %धर्म युद्ध% की तरह पेश कर रहा है, जिसमें ट्रम्प को एक मसीहा के रूप में दिखाया जा रहा है। अमेरिकी सेना के अंदर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कमांडर्स सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करने हेतु बाइबल और %दुनिया के अंत% जैसी धार्मिक बातों का सहारा ले रहे हैं। जहाँ एक तरफ व्हाइट हाउस में पास्टर्स ट्रंप की शक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कैथोलिक धर्मगुरु पोप लियो ने इस युद्ध को नेताओं का अहंकार बताकर इसकी कड़ी निंदा की है। इस वैचारिक मतभेद के कारण ट्रंप और पोप के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है, जिससे यह पूरा संघर्ष अब राजनीति से हटकर धर्म के केंद्र पर आ टिका है। यह स्थिति दिखाती है कि कैसे आधुनिक युद्ध को धार्मिक कट्टरता और आर्मागडन जैसी प्राचीन मान्यताओं से जोड़ा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की वो दूरथ सोशल वाली पोस्ट जिसमें उन्होंने खुद को एक मसीहा की तरह दिखाया। प्रेस में कहा गया हम आपको यानी ईश्वर की कृपा और हमारे सैनिकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारी सशस्त्र सेनाओं में सेवा दे रहे हमारे सारे पुरुषों और महिलाओं के लिए भी हे परमपिता ईश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे राष्ट्रपति ट्रम्प को वो ताकत देते रहे जिसकी उन्हें जरूरत है ताकि वो हमारे महान राष्ट्र का नेतृत्व कर सकें। ओवल ऑफिस से शायद ही पहले किसी युद्ध के बीच इस तरह का वीडियो पब्लिक डोमेन में आया हो। जैसा ट्रंप के लिए प्रार्थना का वीडियो ईरान से जंग के बीच आया।

द गाइडैन की रिपोर्ट में लिखा है अमेरिकी सेना के सैन्य कमांडर्स ईरान वॉर में शामिल होने को सही उद्धारने के लिए सैनिकों के सामने बाइबल के एंड टाइम्स यानी दुनिया के अंत से जुड़ी कट्टर ईसाई बयानबाजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक निगरानी संस्था के पास आई शिकायतों में यह आरोप कमांडर्स पर लगाया गया है। संगठन का नाम मिलिट्री

जिसके बारे में मेरे जैसे लोग इलेक्शन और पीठ के अपॉइंटमेंट से पहले से ही वाच करते आ रहे हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ये भी कह चुके हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक क्रिश्चियन देश है और वही हमारा देश आज भी फाँला करता है। इसके अलावा एक और शब्द पर गौर कीजिए। आर्मागडन जिसका जिक्र यूएस के नांत कमिश्नर्ड ऑफिसर ने अपनी शिकायत में किया था। यह शब्द ईसाई धार्मिक ग्रंथ बाइबल से आता है। बाइबल में आर्मागडन का मतलब उस आखिरी जंग से है जो बुराई और अच्छाई के बीच होगी। अब इसी शब्द का इस्तेमाल अमेरिका में ईरान के खिलाफ जंग के लिए किया जा रहा है।

अमेरिकन अर्थांरिटिज या तो इसे एक धर्म युद्ध की तरह खुद देख रही है या फिर दिखाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अगर कैथोलिक क्रिश्चियन के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो की बातों पर गौर करें तो वो साफ-साफ इस युद्ध के खिलाफ हैं। यही वजह है कि डॉनल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन खुले शब्दों में पोप लियो के खिलाफ बोल रहा है। इस तकरार की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी लेकिन 11 अप्रैल को ये एक बड़े स्तर पर पहुँच गई। तब पोप लियो ने एकदम कड़े शब्दों में कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग सर्वशक्तिमान होने के भ्रम की वजह से बढ़ाई गई है। ट्रंप की ओर इशारा था शायद और उन्होंने इस सोच की निंदा की। साथ ही पोप लियो ने अमेरिकी

नेताओं से जंग रोकने और शांति के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने की मांग की। पोप लियो XIV ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दुनिया को युद्ध और हिंसा की सोच से बाहर निकलना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज दुनिया को जो संदेश सुनने की जरूरत है, वह शांति और संवाद का है। कैमरून की यात्रा पर रवाना लियो ने पोप के विशेष विमान में संवाददाताओं से बातचीत में यह टिप्पणी की। हालांकि, उन्होंने न तो ट्रंप के हालिया सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र किया और न ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के इस सुझाव का कि पोप की धर्मशास्त्र के बारे में बोलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। लियो ने सवालों के जवाब देने से भी परहेज किया। इसके बजाय उन्होंने अल्जीरिया की अपनी यात्रा और हिप्पो के संत ऑगस्टीन की शिक्षाओं के बारे में बात की, जो उनके आध्यात्मिक प्रेरणास्रोत थे। हालांकि, लियो ने कुछ ऐसी टिप्पणियां भी कीं, जिनसे संकेत मिलता है कि उन्होंने ईरान युद्ध को लेकर शांति की अपनी अपील को लेकर ट्रंप प्रशासन की ओर से की गई आलोचनाओं को नजरअंदाज नहीं किया है। ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों में पोप पर लगातार तीखे हमले किए हैं। उन्होंने लियो पर अपराध के खिलाफ कमजोर रुख अपनाने और वामपंथियों के प्रभाव में होने का आरोप लगाया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने पोप के इस रुख पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने हाल के महीनों में हजारों निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मार दिया है और ऐसे देश को परमाणु हथियार हासिल करने देना पूरी तरह अस्वीकार्य है। ल ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दूरस्थ सोशल पर पोप की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि पोप का रुख वास्तविकता से दूर है। ट्रंप ने पहले भी पोप की आलोचना करते हुए उन्हें कमजोर बताया था और माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि वे पोप की राय से सहमत नहीं हैं और अपनी नीतियों पर कायम रहेंगे।

आज का इतिहास

1910 हेली पुच्छल तारे को पहली बार खुली आंखों से देखा गया।
1919 अमेरिका के लेस्ली इरविन ने पैराशूट से पहली बार छलांग लगाई।
1920 जर्मनी और बोल्शेविस्ट ने रूस युद्ध के कैदियों को छोड़ने पर सहमति बनाई।
1927 अमेरिकी अभिनेत्री माए वेस्ट को अपने खेल सेक्स के लिए युवाओं की नैतिकता को गलत बताने के लिए दस दिनों की जेल की सजा सुनाई गई थी।
1934 डेव कोमोनन ने बोस्टन मैरथन जीता।
1943 होलोकोस्ट नाज़ी सैनिकों ने जर्मन कब्जे के खिलाफ पोलैंड में पहली बार बड़े पैमाने पर उत्पात मचाते हुए, शेष यहूदियों को गोल करने के लिए वॉर्सॉ यहूदी बस्ती में प्रवेश किया।
1947 टेक्सास शहर बंदरगाह के पास एक फ्रांसीसी जहाज के फटने से 522 लोग मारे गए।
1948 च्यांग काई शेक चीन के राष्ट्रपति बने।
1960 दक्षिण कोरिया में छात्रों ने एक राष्ट्रव्यापी समर्थक लोकतंत्र विरोधी सिग्मैन री का आयोजन किया, अंततः उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया।
1967 यूरोस्लाव के लेखक मिहलजो मिहलजोव को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।
1972 हंगरी द्वारा संविधान को संशोधित किया गया था।
1982 स्क्रूद्वारा सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन को कक्षा में रखा गया था।
1983 परमाणु परीक्षण फांस द्वारा किए गए थे।
1984 स्कॉटिश मूल के संगीतकार पीटर डोइस मैककार्मिक का एक्वांस ऑस्ट्रेलिया फेयर, एक देशभक्ति गीत, जिसे पहली बार 1878 में प्रदर्शित किया गया था, जिसने आधिकारिक तौर पर गॉड सेव द क्वीन को ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान के रूप में बदल दिया था।
1989 संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेना युद्धपोत आयोवा पर एक बंदूक बर्ज में विस्फोट हो गया, जिसमें 47 नाविक मारे गए।
1993 माउंट कार्मेल सेंटर की 51 दिन की घेराबंदी, वाको, टेक्सास के बाहर ब्रंच डेविडियन धार्मिक संप्रदाय का घर है, जब आग लगाने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।
1995 ट्रक बम से ओखोमा सिटी में संघीय भवन में 168 लोग मारे गए।
1996 पेप्सी कप पर दक्षिण-अफ्रीका ने कब्जा कर लिया था क्योंकि फाइनल में पाकिस्तान को हराया था।
1997 रेनी वंश को 14 वें मिस हवाई हवाई ट्रॉपिक इंटरनेशनल के रूप में तज पहनाया गया था।

क्या ‘सम्राट’ संभाल पाएंगे नीतीश के भरोसे की विरासत?

योगेश कुमार गोयल

बिहार की राजनीति में सत्ता का शिखर छूना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक अपनी सर्वमान्यता सिद्ध करना। सम्राट चौधरी का बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में उदय राज्य के सियासी इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात माना जा रहा है। यह केवल एक व्यक्ति का मुख्यमंत्री बनना नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में उस ‘बड़े भाई’ की भूमिका को आधिकारिक रूप से स्वीकार करना है, जिसका इंतजार पार्टी कार्यकर्ता दशकों से कर रहे थे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद पैदा हुए राजनीतिक शून्य को भरने की जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी के कंधों पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह नीतीश कुमार की उस लंबी और गहरी छाया से बाहर निकल पाएंगे, जिसने पिछले दो दशकों से बिहार की राजनीति को परिभाषित किया है? यही वह कसौटी है, जिस पर अब सम्राट चौधरी को परखा जाएगा।

सम्राट चौधरी का राजनीतिक उदय कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह उनके पिता शकुनी चौधरी की विरासत, और उनके स्वयं के आक्रामक संघर्ष, दशकों की राजनीतिक यात्रा, रणनीतिक धैर्य और समयानुकूल निर्णयों का परिणाम है। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के

लखनपुर में जन्मे सम्राट ने बहुत कम उम्र में ही सत्ता का स्वाद चख लिया था। 1999 में राबड़ो देवी सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री बनने से लेकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर वैचारिक बदलावों और रणनीतिक फैसलों से भरा रहा है। राजद और जदयू जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के साथ काम करने के बाद 2017 में भाजपा का दामन थामना उनके करियर का सबसे निर्णायक मोड़ साबित हुआ। भाजपा ने उनमें एक ऐसे पिछड़ा नेतृत्व (ओबीसी) को देखा, जो न केवल संगठन में जान फूँक सकता था बल्कि राजद के ‘माई’ (एमवाई) समीकरण के सामने एनडीए के ‘लव-कुश’ समीकरण को मजबूती दे सकता था। विशेषकर कुशवाहा समुदाय से आने के कारण सम्राट चौधरी भाजपा के लिए सामाजिक संतुलन का सबसे सटीक मोहरा साबित हुए। भाजपा ने उन्हें न केवल स्वीकार किया बल्कि प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद देकर उनकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा भी जताया। यही भरोसा आज उन्हें मुख्यमंत्री पद तक ले आया है।

मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी की नियुक्ति के साथ ही बिहार की राजनीति में एक दुर्लभ संयोग भी जुड़ा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद वह दूसरे ऐसे नेता बने हैं, जिन्होंने पहले उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी



संभाली और बाद में मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। यह उपलब्धि उनके कद को तो बढ़ाती है लेकिन इसके साथ आने वाली अपेक्षाएं उनके लिए हिमालयी चुनौतियाँ जैसी हैं। नीतीश कुमार केवल एक राजनेता नहीं थे बल्कि वह बिहार के लिए एक ‘इंस्टीट्यूशन’ बन चुके थे। उनके 20 वर्षों के शासनकाल ने राज्य में सुशासन की एक ऐसी परिभाषा गढ़ी, जिसमें महिला सुरक्षा, सड़कें, बिजली और शराबबंदी जैसे मुद्दे हर घर से जुड़े थे। सम्राट चौधरी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि वे स्वयं को नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में पेश करते हैं या एक ऐसी नई पहचान

गढ़ते हैं, जो नीतीश के ‘विकास’ और भाजपा की ‘वैचारिक प्रखरता’ का संगम हो।

अधिकांश राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर एकमत हैं कि नीतीश कुमार जैसा सर्वमान्य नेता बनना सम्राट चौधरी के लिए रातों-रात संभव नहीं होगा। नीतीश कुमार की स्वीकार्यता समाज के हर वर्ग, चाहे वह महादलित हो, अति पिछड़ा हो या आधी आबादी (महिलाएं) हो, में गहराई तक थी। सम्राट चौधरी के पास फिलहाल एक मजबूत सांगठनिक ढांचा और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद है लेकिन उन्हें अपनी ‘आक्रामक छवि’ को अब ‘प्रशासकीय संयम’ में बदलना होगा।

सियासी खींचतान में अटका नारी शक्ति वंदन अधिनियम

नितिन गौतम

नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रभावी बनाने और परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद में पेश कर जो पहल की थी, पर्याप्त समर्थन के अभाव में उसका सदन में गिर जाना प्रत्याशित ही था। हालांकि, इससे यह भी पता चलता है कि राजनीतिक दल अब भी महिला आरक्षण के मुद्दे को प्रक्रियाओं के जाल में उलझाकर आधी आबादी को उनका उचित राजनीतिक हक देने की वास्तविक मंशा से कहीं दूर हैं। आंकड़े अपनी कहानी आप कहते हैं।

सदन में फिलहाल करीब 14 फीसदी महिलाएं हैं, जो काफी निराशाजनक स्थिति है, जिसे बदलने की जरूरत है। किस पार्टी ने महिलाओं पर कितना भरोसा किया, इस पर नजर डालने से साफ हो जाता है कि इस मामले में सभी राजनीतिक दलों की स्थिति कमोबेश एक जैसी ही रही है। वर्तमान संविधान संशोधन विधेयकों को लेकर विपक्ष की मूल चिंता यह थी कि परिसीमन के तहत सीटों का पुनर्निर्धारण दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित कर सकता है, जिस पर सरकार ने आश्वसन देने का प्रयास किया कि सीटों की कुल संख्या बढ़ाने के बावजूद संतुलित प्रतिनिधित्व बना

रहेगा। फिर भी, विधेयकों का गिरना यही संकेत देता है कि राजनीतिक दलों की प्राथमिकताएं अलग हैं। जो महिला आरक्षण, सभी दलों के घोषणापत्रों में शामिल रहा है, उसे प्रक्रियाओं, गणित और क्षेत्रीय हितों के जाल में उलझाने की कोशिश निराशाजनक ही है।

दशकों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को अब केंद्रीय विधि मंत्रालय की आधुनिकता के अनुसार, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के रूप में लागू तो कर दिया गया है, पर देखने वाली बात होगी कि महिला आरक्षण के फायदे वास्तव में सभी महिलाओं को समान रूप से मिल पाते हैं या नहीं। इस मामले में स्थानीय स्व-शासन के निकायों में महिलाओं की भागीदारी के अनुभव से सबक लिया जा सकता है।

कुछ राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों की दृष्टि से देखें, तो विधेयकों का गिरना भी भाजपा के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि उसने यह संदेश देने की कोशिश बखूबी की है कि वह तो महिलाओं को जल्द आरक्षण देना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की वजह से ऐसा नहीं हो सका। अच्छी बात है कि रास्ता खुला है, लेकिन महिला आरक्षण अधिनियम अपने उद्देश्यों में तभी सफल हो सकता है, जब विभिन्न पृष्ठभूमि की महिलाओं को प्रतिनिधित्व का समान मौका मिले।

अमेरिका ईरान युद्धविराम से उभरती नई विश्व व्यवस्था की दिशा

कातिलाल मांडोट

मध्य पूर्व में पिछले चालीस दिनों से जारी तनाव और संघर्ष के बाद जब अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा हुई, तो यह केवल दो देशों के बीच शांति का क्षण भर का प्रयास नहीं था, बल्कि वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में सामने आया। इस संघर्ष ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को चुनौती दी, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी गहरा प्रभाव डाला। ऐसे में यह युद्धविराम आशा की एक किरण के रूप में देखा जा रहा है, किंतु इसके पीछे छिपी जटिलताएं और भविष्य की अनिश्चितताएं भी उतनी ही गंभीर हैं।

इस पूरे घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रम्प की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। उन्होंने इस समझौते को वैश्विक शांति के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया और यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय अचानक नहीं बल्कि कई स्तरों पर कूटनीतिक प्रयासों के बाद संभव हो पाया। इस प्रक्रिया में पाकिस्तान की मध्यस्थता और उसके नेतृत्व, विशेषकर शहबाज शरीफ की पहल को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय शक्तियां अब केवल दर्शक नहीं रह गई हैं, बल्कि वे वैश्विक संकटों के समाधान में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

युद्धविराम से पहले की स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण थी। होर्मुज स्ट्रेट, जो विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख मार्ग है, संघर्ष का केंद्र बन गया था। इस जलडमरूमध्य से तेल और गैस के जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बाधित होने का खतरा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर



सकता था। अमेरिका की ओर से कड़ी चेतावनियां और ईरान की ओर से जवाबी रुख ने स्थिति को और अधिक विस्फोटक बना दिया था। ऐसे में युद्धविराम ने न केवल सैन्य ठकावट को रोका, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता को भी सुनिश्चित करने की दिशा में राहत प्रदान की।

ईरान द्वारा प्रस्तुत दस सूत्रीय प्रस्ताव इस पूरे समझौते का एक महत्वपूर्ण आधार बनकर उभरा है। इस प्रस्ताव में आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने, फ़ौज की गई संपत्तियों की वापसी, क्षेत्र से विदेशी सैन्य बलों की वापसी और युद्ध के स्थायी अंत की मांग शामिल है। यह स्पष्ट करता है कि ईरान केवल अस्थायी शांति नहीं, बल्कि दीर्घकालिक समाधान चाहता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के लिए यह स्थिति एक संतुलन साधने की चुनौती है, जहां उसे अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं और अंतरराष्ट्रीय दबावों के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा।

इस युद्धविराम के बावजूद क्षेत्र में पूर्ण शांति स्थापित होना अभी दूर की बात प्रतीत होती है। इजराइल ने स्पष्ट

कर दिया है कि यह समझौता लेबनान जैसे क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, जहां हिजबुल्लाह के साथ उसका संघर्ष जारी रह सकता है। इससे यह संकेत मिलता है कि मध्य पूर्व का संकट केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कई परस्पर जुड़े हुए संघर्षों का जटिल जाल है।

इस घटनाक्रम में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि भविष्य में कोई स्थायी समझौता होता है, तो इस संस्था पर यह जिम्मेदारी होगी कि वह परमाणु कार्यक्रम से जुड़े नियमों के पालन की निगरानी करे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वैश्विक संस्थाएं आज भी शांति स्थापना में एक केंद्रीय भूमिका निभा सकती हैं, बशर्ते उन्हें सभी पक्षों का सहयोग प्राप्त हो।

भारत सहित कई देशों ने इस युद्धविराम का स्वागत किया है। भारत के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। इसके अलावा वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी एक प्रमुख चिंता का विषय रही है। ऐसे में युद्धविराम से भारत को न केवल आर्थिक बल्कि मानवीय दुष्क्रोण से भी राहत मिली है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस संघर्ष ने वैश्विक राजनीति में शक्ति संतुलन को लेकर नए प्रश्न खड़े किए हैं। चीन की परोक्ष भूमिका और उसकी बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता यह संकेत देती है कि विश्व अब एकध्रुवीय नहीं रहा। विभिन्न शक्तियां अपने-अपने हितों के अनुसार नए गठजोड़ और रणनीतियां बना रही हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय संबंधों का स्वरूप लगातार बदल रहा है। अंततः यह कहा जा सकता है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ यह युद्धविराम केवल एक अस्थायी राहत है, न कि स्थायी समाधान।

भाजपा के राज्यों में सत्ता संधान के अभिनव फंडे...!

अजय बोकिल

बिहार में जिस नफीस अंदाज में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर कथित स्वैच्छिक राजनीतिक वानप्रस्थ में भेजा गया और उनकी जगह सीएम के रूप में भाजपा के सम्राट का राज्याभिषेक किया गया, वह भारतीय जनता पार्टी के अपने राज्यारोहण का चौथा और नवीनतम महाम्राटण है।

इस मायने में आज देश में भाजपा का कोई भी सियासी सानी नहीं है, जिसने सत्ता संधान के इतने विविध तरीके ईजाद किए हों। इसके पहले दलबदल ही पिछले दरवाजे से सत्तासीन होने का एक मात्र फंडा था। जबकि भाजपा के इन फंडों में दबाव, दबंगई, धैर्य, चतुराई, उग्रता, सौम्यता, मित्रता, शत्रुता, अवसरवाद और दीर्घकालीन लक्ष्य सामने रखकर हाइड्रिड चालें चलते रहना भी शामिल है।

राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में इन चालों को बारिकी से देखें तो भाजपा ने हर उस राज्यों में, जहां वह केवल अपने दम पर सत्ता हासिल करने की स्थिति में नहीं है, और जहां अन्य क्षेत्रीय दलों की बैसाखी के बगैरे उसका आगे बढ़ना संभव नहीं है या फिर उन राज्यों में जहां जनसंस्थिकी और जातिवाद का अलग स्ट्रक्चर है, सत्ता में आने के लिए अलग-अलग मॉडल विकसित किए हैं।

बिहार इस मॉडल श्रृंखला का चौथा 'सफल' प्रयोग है। संभव है कि हमें इसका एक और नया प्रयोग पश्चिम बंगाल में देखने को मिले। क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव में भाजपा यूं तो अपने दम पर सत्ता पाने के और ममता बैनर्जी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन खुदा-न-खारता किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला तो वहां भी कोई नया 'खेला' देखने को मिल सकता है।

भारतीय लोकतंत्र में सत्ता हासिल करने के तीन मान्य तरीके रहे हैं। पहला, कोई भी पार्टी चुनाव जीतकर बहुमत के साथ अपने दम पर सत्ता में आ जाए। इस हिसाब से आज देश के आधे से ज्यादा राज्यों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है।

दूसरा है, किसी सत्तासीन या क्षेत्रीय दल की सत्ता को दल-बदल कर गिरा दिया जाए और हर मुमकिन जोड़तोड़ कर अपनी सरकार बनाई जाए, जैसे कि मध्यप्रदेश में 6 साल पहले हुआ।

तीसरा, महाराष्ट्र मॉडल है, जहां पहले किसी सहयोगी दल का सीएम बनकर भाजपा उसे कंधा दे और चुनाव करवाकर खुद उसके कंधे पर सवार हो जाए। चौथा है, बिहार मॉडल। जहां सियासी हालात को अपने अनुकूल ढलाने तक का लंबा इंतजार किया जाए और कंधा देते-देते धीरे से सवार को उतारकर खुद पालकी में विराजमान हुआ जाए और यह सब कुछ लखनवी फायासत के साथ किया जाए कि कोई उफ् तक न कर सके और इसे नियति का चक्र मानकर खुद हाथ में झांझ-मंजीरे थाम बैठे। हालांकि,



यह मॉडल मप्र मॉडल के ठीक विपरीत है, जहां भाजपा ने मामूली बहुमत से सत्तारूढ़ हुई कांग्रेस की तत्कालीन कमलनाथ सरकार में ही संधे लगा दी और पार्टी की अंतर्कलह को अपने पक्ष में भुना लिया। या यूं कहे कि मोटे तौर पर पहले ही भगवा रंग में रंग चुके मप्र में सत्ता संचालन में आया यह मामूली 'ब्रेक' था, जिसे सियासी हिकमत के साथ 'ठीक' कर लिया गया। इस दृष्टि से भाजपा में 'हिकमत' शब्द की व्याख्या बहुत व्यापक है। इसमें 'साम-दाम-दंड-भेद' सब जायज है और इस राजनीतिक नैतिकता के पैमाने की भी 21 वीं सदी की भाजपा के हैं। इसके आगे दूसरी राजनीतिक पार्टियां लगभग बेवस नजर आती हैं।

उनके सामने दो ही विकल्प हैं। या तो वो भाजपा के साथ, उसकी शर्तों पर उसके दास बनकर रह लें या फिर सत्ता गंवाने के लिए तैयार रहें। चूंकि राजनीति का अंतिम ध्येय सत्ता है और वो कैसे हासिल की जाती है, यह सवाल नैतिक होते हुए भी अदम्य सत्ताकांक्षा के आगे गौण है। भाजपा का इसमें पूरा विश्वास है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि अब भाजपा के कोर एजेंडे के सभी मुद्दे पूरे हो चुके हैं। इसलिए सत्ता संधान के लिए नया धनुष और बाण चाहिए। भाजपा अंतिम कोर मुद्दा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का है, जिसे उसने अलग तरीके से राज्यवार लागू करना शुरू किया है। संभव है कि अगले लोकसभा चुनाव तक इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाए।

कश्मीर से धारा 370 हटाने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के एजेंडे पूरे हो ही चुके हैं। यानी इनके बूते अब मतों के दोहन की संभावना नहीं के बराबर है। इन भावनात्मक मुद्दों से हटकर पार्टी महिलाओं को सीधे नकदी जैसे तरीकों का आज़मा रही है, जो जमीनी स्तर पर राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा फलदायी सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन ये उपाय सत्ता परिवर्तन के पुराने फंडे से प्रेरित हैं कि जनादेश हासिल कर सत्ता में आया जाए और फिर इसी के सहारे अंगद के पांव को तरह जमा जाए। हालांकि इस काम में विकास, हिंदुत्व, समान अधिकार, सुशासन, समरसता आदि अनुषांगिक घटक हैं।

जहां तक बिहार की बात है तो वहां सत्ता सीधे अपने हाथ में लेने के लिए भाजपा ने माफिक गजब का धैर्य दिखाया है। ढेर से ही सही, वह घड़ी आ गई कि पटना में

घी के दीए जलाए जाएं। नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के राज में ज्यादातर समय भाजपा के सहारे ही राजनीति की और सुशासन बाबू की छवि गढ़ी। क्योंकि लालू राज में बिहार गवर्नर्स के पाताल में चला गया था। ऐसे में वहां के लोगों को नीतीश कुमार का 'सुशासन' भी राम राज की तरह लगने लगा। यह बात अलग है कि नीति आयोग के विकास के तमाम पैमानों पर बिहार आज भी सबसे निचली पायदान पर है। विकास की दौड़ में यूपी और एमपी भी उससे काफी आगे निकल गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह उस राज्य की हालत है, जिसे देश का सर्वाधिक राजनीतिक चेतना वाला प्रदेश कहा जाता है। वहां से कई कांतिकारी आंदोलन उठे। इन आंदोलनों ने दूसरे राज्यों को तो बदल दिया, लेकिन 'दिया तले अंधेरे' की तर्ज पर बिहार जहां का तहां रहा। यह बिहार का दुर्भाग्य है कि वहां इस मुखर राजनीतिक चेतना की भौतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास की चेतना से आदर्श जुगलबंदी कभी भी नहीं हो सकी।

बहरहाल, राज्य के नए और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भी यह जुगलबंदी आगे हो सकेगी या नहीं, कहना मुश्किल है। बताया यही जा रहा है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की भी पसंद हैं, क्योंकि वह अति पिछड़ी कोइरी जाति से आते हैं। लेकिन इस 'जातीय फिक्स्ड डिवायजिट' से कोई बुनियादी मसला हल नहीं होता। सम्राट अपनी जातीय पूंजी को राज्य के विकास में कैसे निवेश करते हैं, यह देखने की बात है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि राज्य में डबल इंजिन की सरकार बनने से विकास की गति और दिशा तेज होगी। लेकिन खतरा यह भी है कि बिहार में धार्मिक आधार पर ध्ववीकरण और तेज हो सकता है।

सम्राट चौधरी इस पर कैसे नियंत्रण रखते हैं, यह भी देखना होगा। वैसे सम्राट को स्वीकारने में बिहार के सभी समुदायों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी चाहिए, क्योंकि वो भाजपा के पहले मुख्यमंत्री भले हों, लेकिन वो संघ की पाशाला के विद्यार्थी नहीं रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सम्राट भी एक सदी कालीन एजेंडे के तहत तात्कालिक व्यवस्था है। इस 'मोर्चा' को भी दिखी के तख्त का हुकुम ही मानना होगा और भाजपा का खांटी राष्ट्रवादी नेतृत्व तैयार होने तक राज्य का रथ हांकना होगा। वैसे भी बिहार से नीतीश की विदाई मंडलवाद, समन्वयवाद, राजनीतिक हिंडोलावाद (कभी इधर तो कभी उधर), अति पिछड़ावाद और सियासी सौम्यता की भी विदाई है। अब देखना यह है कि बिहार किस राज्य को फॉलो करता है, यूपी को, गुजरात को, मप्र को अथवा असम को। आगे की सियासत यह भी तय करेगी कि भाजपा सत्ता में आने अथवा बने रहने का कोई चौथा फार्मूला भी विकसित करेगी या नहीं।

जॉर्जिया मेलोनी पर इतना क्यों भड़के हुए हैं ट्रंप?

निरज कुमार दुवे

छह महीने पहले शर्म अल शेख के मंच पर खड़ी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिस राजनीतिक रिश्ते को वह अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रही हैं, वही उनके लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाएगा। उस मंच पर डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी तारीफों के पुल बांधे, उन्हें सुंदर बताया, लेकिन वही ट्रंप आज उनके साहस पर सवाल उठा रहे हैं। यह कहानी सिर्फ दो नेताओं के ठकावट की नहीं है, बल्कि यह बदलती वैश्विक राजनीति, युद्ध की भयावहता और जनता की बेचैनी की कहानी है। हम आपको बता दें कि ट्रंप और मेलोनी का रिश्ता शुरुआत से ही विचारधारा पर टिका था। दोनों राष्ट्रवादी राजनीति के चेहरे रहे, दोनों ने सख्त प्रवासन नीतियों का समर्थन किया और दोनों खुद को मजबूत नेता के रूप में पेश करते रहे। मेलोनी ने तो ट्रंप के करीब आने के लिए हर संभव प्रयास किया। वह उनके फ्लोरिडा स्थित आवास तक गई और यूरोप के इकलौती नेता बनीं जो उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुईं। लेकिन राजनीति में रिश्ते उतनी ही तेजी से टूटते हैं जितनी तेजी से बनते हैं। ईरान युद्ध ने इस रिश्ते की असलियत सामने ला दी। ट्रंप चाहते थे कि इटली अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध में खुले तौर पर शामिल हो, लेकिन मेलोनी ने साफ इंकार कर दिया। यही वह मोड़ था जहां से ट्रंप का रवैया बदल गया। उन्होंने मेलोनी को कायर तक कह दिया और आरोप लगाया कि वह ईरान के परमाणु खतरे को गंभीरता से नहीं ले रहीं। यह हमला सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत भी था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब ट्रंप ने पोप लियो पर हमला किया और उन्हें कमजोर बताया, तब मेलोनी ने इसे अस्वीकार्य कहा। यह बयान भले ही दबाव में दिया गया हो, लेकिन इसका असर गहरा था। इटली एक ऐसा देश है जहां पोप का सम्मान बेहद गहरा है और जनता युद्ध के खिलाफ खड़ी रहती है। ऐसे में मेलोनी ने पहली बार खुलकर ट्रंप के खिलाफ आवाज उठाई।

विश्लेषकों का मानना है कि यह ठकावट मेलोनी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हाल ही में हुए जनमत संग्रह में उनकी सरकार को करारी हार मिली थी। जनता में असंतोष बढ़ रहा था और ईरान युद्ध की वजह से बढ़ती महंगाई ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी थीं। ऐसे समय में ट्रंप से दूरी बनाना उनके लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। इसीलिए मेलोनी ने धीरे धीरे अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। उन्होंने ईरान युद्ध



में भागीदारी से इंकार किया, सिसिली के सैन्य अड्डे के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी और इजराइल के साथ रक्षा समझौते को भी रोक दिया। यह सब संकेत हैं कि वह अब खुद को एक संतुलित और स्वतंत्र नेता के रूप में पेश करना चाहती हैं। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं है। मेलोनी अभी भी एक पतली रस्सी पर चल रही हैं। एक तरफ उन्हें अमेरिका के साथ अपने पुराने रिश्ते को पूरी तरह तोड़ना नहीं है, दूसरी तरफ उन्हें घरेलू राजनीति में अपनी छवि सुधारनी है। यही वजह है कि उनके बयान कई बार संतुलित और अस्पष्ट नजर आते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू है हंगरी के नेता विक्टर ओबॉन की हार। ओबॉन ट्रंप के करीबी सहयोगी माने जाते थे। उनकी हार ने मेलोनी को यह संकेत दिया कि ट्रंप के साथ खड़े रहना अब राजनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है। देखा जाये तो इटली की जनता की प्राथमिकताएं साफ हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय राजनीति से ज्यादा अपने घरेलू मुद्दों की चिंता है। बढ़ती गैस की कीमतें, महंगाई और आर्थिक दबाव उनके लिए असली मुद्दे हैं। ऐसे में अगर मेलोनी सिर्फ वैश्विक मंच पर बयान देती रहें और घरेलू समस्याओं का समाधान न कर पाएं, तो उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। हालांकि अभी भी उनकी पार्टी और उनका नेतृत्व चुनावी संघर्ष में आगे है, लेकिन यह बहुत स्थायी नहीं है। इटली में विपक्ष भले ही बिखरा हुआ हो, लेकिन अगर उसने एक मजबूत विकल्प पेश कर दिया तो समीकरण बदल सकते हैं। देखा जाये तो यह साफ है कि मेलोनी एक बड़े राजनीतिक मोड़ पर खड़ी हैं। ट्रंप से दूरी बनाना उनके लिए एक रणनीतिक कदम है, लेकिन असली चुनौती घरेलू मोर्चे पर है। अगर वह जनता की आर्थिक परेशानियों को दूर नहीं कर पाईं, तो कोई भी चाल उनकी राजनीति को बचा नहीं पाएगी। बहरहाल, यह पूरा घटनाक्रम एक कड़वा सच उजागर करता है। वैश्विक राजनीति में दोस्ती स्थायी नहीं होती, हित स्थायी होते हैं। और जब हित ठकावटें हैं, तो सबसे मजबूत रिश्ते भी टूट जाते हैं। मेलोनी और ट्रंप की कहानी इसका ताजा उदाहरण है।

उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर टाले अकाल मृत्यु और दिलाए मोक्ष

दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग-शंकर जी का यह अनोखा मंदिर अन्य प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में एक मात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि दक्षिण दिशा के स्वामी स्वयं भगवान यमराज हैं। तभी जो भी व्यक्ति इस मंदिर में आ कर भगवान शिव को सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे मृत्यु उपरांत यमराज द्वारा दी जाने वाली यातनाओं से मुक्ति मिलती है।

अकाल मृत्यु टालते हैं शिव जी-देश-दुनिया से काफी लोग यहां पर इसलिये भी दर्शन करने आते हैं कि जिससे वे अपनी अकाल मृत्यु को टाल सकें और सीधे मोक्ष को प्राप्त कर सकें।

सारी इच्छा करते हैं पूरी-भगवान शिव अपने भक्त की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अगर आपको अपनी मनोकामनाएं पूरी



धन, धान्य, निरोगी शरीर, लंबी आयु, संतान आदि सब कुछ प्राप्त हो। पृथ्वी का केंद्र हैं महाकाल-कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु है और संपूर्ण पृथ्वी के राजा भगवान महाकाल यहीं से पृथ्वी का भरण-पोषण

करते हैं। गाय के कंडे से होती है भस्मार्ती-यहां पहले महाकाल की भस्म आरती में ताजा मुर्दे की भस्म का ही प्रयोग होता था, किन्तु महात्मा गांधी के आग्रह के पश्चात शास्त्रीय विधि से निर्मित उपल-भस्म से भस्मार्ती होने लगी।

हनुमान जी के गुणों से आलोकित करें जीवन

मनोजवं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमना वरिष्ठम्।
वातात्मजं वानरयूथं मुयंश्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये॥

यदि हम खुद को हनुमान जी का सच्चा भक्त मानते हैं, तो हमें ऐसे महान चरित्र के चारित्रिक गुणों के प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित करने का प्रयास करना चाहिए।

उक्त श्लोक द्वारा हमें सर्वतोमुखी शक्ति के प्रतीक हनुमान जी का यथार्थ चित्रण मिलता है की कैसे वे शरीर के साथ-साथ मन से भी अपार बलशाली थे एवं उन्होंने वासना को जीत लिया था। वे जितेन्द्रिय थे और बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठतम थे। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भारत के लोगों के मन में हनुमान जी का चरित्र उनकी ईश्वर भक्ति, ईश्वर सेवा और ईश्वर के प्रति वफादारी के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसलिए ही यहां के अधिकतर घरों में उनकी मूर्ति प्रतिदिन पूजी जाती है और देश के कोन-कोने में भी उनके अनगिनत मंदिर बने हुए हैं। जन के दिलों में स्थान पाने वाले हनुमान जी की पूजा-अर्चना करना उनके प्रति हमारी श्रद्धा का एक पहलू है, लेकिन उनके चारित्रिक गुणों से प्रेरणा लेना व उनके गुणों को जीवन

में आत्मसात करना सर्वथा दूसरा पहलू है। अतः यदि हम खुद को हनुमान जी का सच्चा भक्त मानते हैं, तो हमें ऐसे महान चरित्र के चारित्रिक गुणों के प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित करने का प्रयास करना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन जन्मे हनुमान जी के यूँ तो अनेक नाम हैं, परन्तु सर्वाधिक प्रचलित हनुमान शद का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो मान का हनन करने वाला हो। पौराणिक कथाकारों के अनुसार ज्ञानसूर्य परमात्मा के ज्ञान गुण शक्तियों को अपनी बुद्धि में समाहित करने वाले हनुमान जी अनेक आध्यात्मिक शक्तियों से सुसंपन्न रहे, लेकिन अपनी किसी भूल के कारण उन्हें यह शाप मिला कि समय आने पर वे अपनी शक्तियों को भूल जायेंगे और किसी के द्वारा याद दिलाये जाने पर वे शक्तियां जाग्रत हो उठेंगी। अब यह तो हम सब भलीभांति जानते ही हैं कि शाप देने का कार्य कोई श्रेष्ठ व्यक्ति तो कर नहीं सकता, क्योंकि क्योंकि शाप या बददुआ देने वाली तो माया है, अर्थात् पांच विकार, तो इसका अर्थ यह हुआ की कलियुग के अंत में जब हम सभी आत्माएं माया द्वारा शापित होकर मूर्च्छित हो जाती हैं और अपनी समस्त शक्तियां खो देती हैं, तब सर्वशक्तिमान परमात्मा हमें ज्ञान संजीवनी द्वारा फिर से सुरजीत करते हैं और माया के शाप से हमें सदा के लिए मुक्त कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप हम अपनी सर्व



याचना की बजाय गुणों को धारण करें :

संसार की आत्माएं तो हुनमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि की पूर्ति की कामना हेतु स्वाथर्वश याद करती हैं, परन्तु वर्तमान समय की मांग यह है कि हम समय की नाजुकता को पहचान कर हनुमान जी से याचना करने की बजाय उन जैसे गुणों को धारण करके अनेक याचक आत्माओं की कामना पूर्ति करें और श्री हनुमान जी के गुणों की रोशनी से अपने जीवन-पथ को आलोकित करें। उनके समान ईश्वर प्रेम में रम जाएं और उनके समान ईश्वर समर्पित होकर ईश्वर समान बन जाएं।

पर अवतरित हो चुके हैं। ऐसे समय त्याग, तपस्या और सेवा को जीवन मद्दगार बनने वाली आत्माओं का में भगवान श्री हनुमान जी की तरह में धारण करके ईश्वरीय सेवा में भगवान आहान कर रहे हैं।

क्यों अपनी ही पुत्री की ओर आकर्षित हुए ब्रह्मा

सरस्वती का अर्थ होता है बहाव। यह बहाव केवल पानी का नहीं बल्कि विद्या और कला का भी है। यही वजह है कि इन्हें विद्या और कला की देवी भी कहा जाता है। सरस्वती के द्वारा विज्ञान, संगीत और कविताओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में सरस्वती को दैवीय नदी की भी संज्ञा दी गई है। साथ ही इन्हें पवित्रता और उर्वरता की देवी भी कहा गया है। सरस्वती को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जिनमें भागेश्वरी, सतरूपा, ब्राहमी, पृथुदर, बकदेवी, बिरज, शारदा आदि प्रमुख हैं। हिन्दू धर्म से जुड़े पौराणिक इतिहास पर नजर डालें तो कई ऐसी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जिनसे अभी तक आमजन वाकिफ नहीं हैं। विस्तृत इतिहास होने की वजह से कुछ घटनाएं छूट जाती हैं तो कुछ नजरअंदाज कर दी जाती हैं। इन्हीं कहानियों में से एक हैं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की घटना। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि त्रिदेव के हाथों में ही इस सृष्टि की बागडोर समाहित है। ब्रह्मा के पास सृष्टि की रचना का दायित्व है तो विष्णु के पास संरक्षण का, वहीं देवों के देव कहे जाने वाले महादेव शिव को विनाश का जिम्मा सौंपा गया है। इसी विनाश के बाद फिर से शुरू होता है सृजन का चक्र। ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की इस घटना का उल्लेख सरस्वती पुराण में वर्णित है। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने

सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई मां नहीं केवल पिता, ब्रह्मा थे। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थीं कि स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारो दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति-पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया था स्वयंभु मनु। इसके उलट मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के पांच सिर थे। कहा जाता है जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सान्ध्य, ब्राहमी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना, सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारो दिशाओं में छिपती रहीं लेकिन वह उनसे नहीं बच पाई इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई लेकिन अपने पांचवें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में ही खोज



निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उसके साथ संभोग करने के सभी देवताओं की नजरों में अपराध

था। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिव से आग्रह किया कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के लिए यौनाकांक्षाएं रखीं, जोकि एक बड़ा पाप है, ब्रह्मा को उनके किए का फल मिलना ही चाहिए। क्रोध में आकर शिव ने उनके पांचवें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया था। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के सर्वप्रथम पांच सिर थे। लेकिन जब अपने पांचवें मुख से उन्होंने सरस्वती जोकि उनकी पुत्री थी, को उनके साथ संभोग करने के लिए कहा तो क्रोधावश सरस्वती

ने उनसे कहा कि तुम्हारा यह मुंह हमेशा अपवित्र बातें ही करता है जिसकी वजह से आप भी विपरीत ही सोचते हैं। इसी घटना के बाद एक बार भगवान शिव, अपनी अर्धांगिनी पार्वती को ढूँढते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे तो पांचवें सिर को छेड़कर उनके अन्य सभी मुखों ने उनका अभिवादन किया, जबकि पांचवें मुख ने अमंगल आवाजें निकालनी शुरू कर दी। इसी कारणवश क्रोध में आकर शिव ने ब्रह्मा के पांचवें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया।

दुर्योधन को भी दिए थे श्रीहरि ने विराट रूप में दर्शन



विश्वरूप या कहें भगवान विष्णु का विराट स्वरूप का उल्लेख भगवद्गीता के अध्याय 11 में है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में विश्वरूप दर्शन कराते हैं। लेकिन उन्होंने इस रूप में पहले भी अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं।

पुराणों में उल्लेख मिलता है। भगवान विष्णु ने अपने इस रूप के दर्शन लक्ष्मी जी को करवाए थे। हालांकि कि इस बारे में अलग-अलग पुराणों में अलग-अलग जानकारी मिलती है। भगवान विष्णु के परम भक्त नारद जी को भी

उन्होंने अपने विराट स्वरूप के दर्शन दिए हैं। भगवान विष्णु के भक्त प्रहाद के वंशज थे राजा बलि। जिनको भगवान विष्णु ने वामन अवतार में विराट स्वरूप के दर्शन दिए थे। द्वापर युग में जब भगवान श्रीकृष्ण के रूप में भगवान विष्णु

ने अवतार लिया तब उन्होंने अपनी मां यशोदा को भी इसी विराट स्वरूप में दर्शन दिये थे। महाभारत में दुर्योधन और विश्वरूप दर्शन वर्णित है। कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान अर्जुन को विराट रूप के दर्शन दिए।

भगवान विष्णु के अन्य नाम :

उग्र, शर्व, भगवत, नारायण, कृष्ण, वैकुण्ठ, विष्टरश्रवस्, जिन, हृषिकेश, केशव, माधव, स्वधु, दैत्यारि, पुण्डरीकाक्ष, गोविन्द, गरुडध्वज, पीताम्बर, अच्युत,

शार्गि, विष्वक्सेन, जनार्दन, दामोदर, इन्द्रावरज, चक्रपाणि, चतुर्भुज, पद्मानाभ, मधुरिपु, भीम, त्रिविक्रम, देवकीनन्दन, शौरि, श्रीपति, पुरुषोत्तम, वनमालिन, बलिध्वंसिन, कंसाराति, अधोक्षज,

विश्वम्भर, कैटभजित, विधु, श्रीवत्सलाञ्छन, पुराणपुरुष, यज्ञपुरुष,नरकान्तक, जलशायिन्, मुकुन्द, उपेन्द्र, मुरमर्दन, राम, वामन, नरसिंह, वराह और भविष्य में होने वाला अवतार कल्कि यह अवतार भगवान विष्णु का ही अवतार है।

घर में इसलिए रखते हैं हरे पौधे

घर में यदि आप हरे पौधों को रखते हैं, तो यह घर के वास्तु दोषों को दूर करने में सहायक होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा तुलसी के पौधे को महत्व दिया जाता है। तुलसी के पौधे से जब हवा स्पर्श कर बहती है, तब वह घर के पर्यावरण को भी स्वस्थ रखती है। प्रदूषण और रोग निवारण में तुलसी का पौधा औषधि है। इस घर में अवश्य ही लगाएं। ठीक इसी

तरह पृथ्वी के नीचे कहीं-कहीं निगेटिव स्ट्रीम (छिर) होती है। यदि यह स्ट्रीम दुकान या फैक्ट्री पर हो तो गंभीर रोगों से प्रभावित हो सकती है। यह गंभीर रोग जैसे हृदय रोग, मधुमेह, लकवा और कैंसर हो सकते हैं। तुलसी का पौधा यदि घर में है तो यह स्ट्रीम निष्क्रिय हो जाती है। हरे पौधे विकास का प्रतीक भी माने जाते हैं। जो घर के अंदर

रखने से मंगलमय यानी सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं। ठीक इसी तरह वास्तु शांति के लिए घर के अंदर हवन भी हर माह जरूर करवाना चाहिए। हवन का धुंआ घर में उपस्थित निगेटिव एनर्जी, वास्तु दोषों के साथ रोग फैलाने वाले कीटाणुओं का भी अंत कर देता है। जिससे



कि आपकी ज़िंदगी खुशनुमा तरीके से व्यतीत होती है।

इन उपायों से होगी आपकी कई मनोकामनाएं पूरी

हमारे जीवन में सुख दुख तो लगा रहता है जिस कारण हम परेशान ही होते हैं। सभी चाहते हैं कि उसके जीवन में खुशहाली रहे और सुख-शांति बनी रहे पर हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। जीवन में सुख और शांति का बना रहना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में कुछ उपायों को अपनाकर शायद हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तुलसी के पौधे को प्रतिदिन

जल चढ़ाएं तथा गाय के घी का दीपक लगाएं। रविवार को पुष्य नक्षत्र में श्वेत आक की जड़ लाकर उससे श्रीगणेश की प्रतिमा बनाएं फिर उन्हें खीर का भाग लगाएं। लाल कनेर के फूल तथा चंदन आदि के उनकी पूजा करें। तत्पश्चात गणेशजी के बीच मंत्र (ॐ गं) के अंत में नमः शब्द जोड़कर 108 बार जप करें। सुबह गौरी-शंकर रुद्राक्ष शिवजी के मंदिर में चढ़ाएं। सुबह बेल पत्र (बिल्व) पर सफेद

चंदन की बिंदी लगाकर मनोरथ बोलकर शिवलिंग पर अर्पित करें। बड के पत्ते पर मनोकामना लिखकर बहते जल में प्रवाहित करने से भी मनोरथ पूर्ति होती है। मनोकामना किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। नए सूती लाल कपड़े में जटावाला नारियल बांधकर बहते जल में प्रवाहित करने से भी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इन प्रयोगों को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी

हो जाएंगी। सुबह घर से काम के लिए निकलने से पहले नियमित रूप से गाय को रोटी दें। एक पात्र में जल लेकर उसमें कुंकुम डालकर बरगद के वृक्ष पर नियमित रूप से चढ़ाएं। सुबह घर से निकलने से पहले घर के सभी सदस्य अपने माथे पर चन्दन तिलक लगाएं। मछलियों की आटे की गोली बनाकर खिलाएं। चींटियों को खोपरे व शकर का बूरा मिलाकर खिलाएं। शुद्ध कस्तूरी को चमकोले पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें।

जदयू अध्यक्ष नीतीश सीएम सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को 5, देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम विजय चौधरी भी मौजूद थे। सम्राट चौधरी ने दोनों नेताओं का स्वागत किया। इस दौरान नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच 15 मिनट तक बातचीत हुई। मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें नीतीश कुमार मुस्कुराते दिख रहे हैं। उन्होंने फिर से सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा। सम्राट चौधरी ने भी दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमन किया। बिहार में नई सरकार बनने के बाद यह पहला मौका है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्री से मुलाकात करने गए। नीतीश कुमार ने तीनों नेताओं ने बधाई दी और कहा कि अच्छे से काम करते रहिए आपलोग। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, सरकार के कामकाज और आने वाले समय की रणनीति को लेकर चर्चा हुई।

महिला विरोधी रुख पर दिल्ली सीएम रेखा ने विपक्ष को घेरा

नईदिल्ली। दिल्ली को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पारित नहीं होने के बाद शनिवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके “महिला विरोधी” रुख पर उनके निर्वाचन क्षेत्रों की हर महिला सवाल उठाएगी। गुप्ता ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “विपक्ष ने तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर महिलाओं को लोकसभा तक नहीं पहुंचने देंगे। सच यह है कि उन्हें केवल अपने परिवार की महिलाओं की चिंता है, देश की 70 करोड़ महिलाओं की नहीं।” उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, “वे नहीं चाहते कि देश की आधी आबादी संसद तक पहुंचे। विपक्ष के महिला विरोधी रुख पर उनके निर्वाचन क्षेत्रों की हर महिला सवाल उठाएगी।” उन्होंने कहा, “1971 में देश की आबादी करीब 50 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 140 करोड़ हो गई है। उस हिसाब से सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए।

तमिलनाडु सीएम ने परिसीमन बिल को बताया काला कानून

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 की विफलता का जश्न मनाते हुए इसे परिसीमन नामक काले कानून के खिलाफ जीत बताया। उन्होंने विधेयक को हराने में भूमिका निभाने के लिए इंडिया गठबंधन के सांसदों और महिला सांसदों को धन्यवाद दिया। स्टालिन ने कहा कि राज्य सरकार और विपक्षी नेताओं ने लगभग एक साल पहले ही इस मुद्दे का अनुमान लगा लिया था और प्रस्तावित कानून की प्रतियां जलाने सहित विरोध प्रदर्शनों का एक समन्वित अभियान चलाया था, जिससे सार्वजनिक रूप से और संसद के भीतर भी प्रतिरोध पैदा करने में मदद मिली। एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में स्टालिन ने कहा कि मैं आपके सामने खुशी और नई ऊर्जा के साथ खड़ा हूं। परिसीमन नामक काले कानून के खिलाफ हमारा संघर्ष सफल रहा है।

पश्चिम बंगाल चुनाव में असम भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत

कोलकाता। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले प्रचार करने के लिए असम राज्य भाजपा का 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 16 अप्रैल को पश्चिम बंगाल पहुंचा। ये चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने वाले हैं। असम प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल के कई निर्वाचन क्षेत्रों में व्यापक प्रचार अभियान चलाने की योजना बना रहा है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं और एक ही दिन में कूच बिहार, कालचीनी और फांसिदेवा विधानसभा क्षेत्रों में तीन विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कैबिनेट मंत्री पीयूष हजारिका, जयंता मल्लभारुआ, रणजीत कुमार दास, बिमल बोरा, डॉ. रानोज पेगु, रूपेश गोवाला, कृपानाथ मल्लाह, राजदीप रॉय, कृष्णेंद्र पॉल, कौशिक राय, सांसद परिमल सुकलाबैद्य, कई विधायक और राज्य के वरिष्ठ नेता सहित कई प्रमुख नेता चुनाव प्रचार का नेतृत्व करने के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव भाजपा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

संसद में तमिलनाडु की आवाज दबाना चाहती है भाजपा : राहुल

नईदिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि परिसीमन से संबंधित हालिया संसदीय कदम का उद्देश्य संसद में तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व को कम करना है। आगामी चुनावों से पहले राज्य में अपना प्रचार अभियान तेज करते हुए उन्होंने यह बात कही। तिरुवन्नूरु जिले के पोनेरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी ने इस कदम को दक्षिणी राज्यों को प्रभावित करने वाली एक व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बताया। क्षेत्रीय चिंताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और भाजपा राज्य की पहचान को निशाना बना रहे हैं। राहुल ने कहा कि स्वाभाविक रूप से, वर्षों से मेरा तमिलनाडु के लोगों के साथ एक रिश्ता बन गया है। मेरा जन्म तमिलनाडु में नहीं हुआ है, और मेरा परिवार भी तमिलनाडु से नहीं है, फिर भी मैं खुद को तमिलनाडु का ही मानता हूं। आरएसएस और भाजपा तमिलनाडु, तमिल भाषा और तमिल संस्कृति पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं।

महिला आरक्षण विधेयक को लेकर पक्ष और विपक्ष में सियासी घमासान तेज

कांग्रेस की महिला-विरोधी सोच हुई उजागर : किरेन रिजिजू

नईदिल्ली। महिला आरक्षण विधेयक के लोकसभा में पारित न हो पाने के बाद, मोदी सरकार को 2014 के बाद पहली बार विधायी विफलता का सामना करना पड़ा। इसके एक दिन बाद, शनिवार को सरकार ने विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि शुक्रवार को जो हुआ, उससे कांग्रेस की महिला-विरोधी मानसिकता स्पष्ट होती है। सरकार की ओर से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जोरदार हमला बोला और कहा कि विपक्ष को इसके लिए लोकतांत्रिक रूप से दंडित किया जाएगा।

किरेन रिजिजू ने कहा कि बजट सत्र आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। यह एक अत्यंत फलदायी बजट सत्र रहा। केंद्रीय बजट सफलतापूर्वक पारित हो गया। दूसरे सत्र में, प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में पश्चिम एशिया के संकट पर बयान दिया। बजट सत्र को तीन दिनों के लिए 16, 17 और 18 अप्रैल तक बढ़ाया गया था। इन तीन दिवसीय विशेष सत्रों के दौरान, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन संशोधन विधेयक पेश किए गए। हमारे पास बहुमत है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया, इसलिए यह विधेयक पारित नहीं हो सका। सरकार के अन्य सभी विधेयक पारित हो गए।

रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में विधेयक के विफल होने से सरकार निश्चित रूप से निराश है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यह न तो केंद्र सरकार की विफलता है और न ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की। उन्होंने कहा कि यह सबके लिए काला दिन है और कांग्रेस जिस तरह से जश्न मना रही है वह शर्मनाक और निंदनीय है। हालांकि, रिजिजू ने कहा कि संसद सत्र बेहद सफल रहा और उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी को धन्यवाद दिया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रिजिजू ने कहा कि अगर राहुल गांधी कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण देना असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है, तो किसी को राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि महिलाओं को अधिकार देना कठिन और लोकतंत्र को कमजोर करना है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता।

महिला आरक्षण पर राजीव रंजन का कांग्रेस पर बड़ा हमला

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने शनिवार को लोकसभा में संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 के पारित न हो पाने के बाद विपक्ष की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल में बाधा डाली है और जोर देकर कहा कि महिला मददाता इस घटनाक्रम पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देंगी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा विधेयक की हार को लोकतंत्र की जीत करार देने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सिंह ने कहा कि विपक्ष उस ऐतिहासिक पहल को झटका दे रहा है जिसे उन्होंने महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पहल बताया।

सिंह ने मीडिया को बताया कि विपक्ष का कहना है कि इस विधेयक का गिरना एक ऐतिहासिक कदम है। उनके अनुसार, यह ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि उन्होंने देश में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों को विफल कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करके देश की लगभग आधी आबादी वाली महिलाओं को न्याय दिलाना था।

नईदिल्ली। महिला आरक्षण विधेयक के लोकसभा में असफल होने के बाद सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा ने शनिवार को कहा कि संवैधानिक संशोधन विधेयक केंद्र सरकार की %षड्यंत्र% है, जिसका उद्देश्य देश में हमेशा के लिए शासन करना और लोकतंत्र को कमजोर करना है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पर भारी अंतरराष्ट्रीय दबाव है, जो %स्पष्ट% हो चुका है और जनता को साफ दिखाई दे रहा है।

नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका ने कहा कि सरकार ने परिसीमन के लिए यह विधेयक लाया था, जिसके बारे में विपक्ष का आरोप है कि इससे दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्य कमजोर होंगे। हालांकि, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकसभा में विधेयक की विफलता %लोकतंत्र की जीत% है और विपक्ष की एकता को दर्शाती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कल जो हुआ वह लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। संघीय ढांचे को बदलने और लोकतंत्र को कमजोर करने की सरकार की साजिश नाकाम हो गई और रुक गई।

उन्होंने दावा किया कि यह संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी, और यह सत्ताधारी दल के नेताओं के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। मुझे लगता है कि यह एक साजिश है कि उन्हें किसी भी तरह सत्ता में बने रहना है। इसलिए, इसे हासिल करने के लिए, वे महिलाओं का इस्तेमाल करके स्थायी रूप से सत्ता में बने रहने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि अगर यह पारित हो गया, तो वे जीत जाएंगे। अगर यह पारित नहीं हुआ, तो वे अन्य दलों को महिला विरोध करने खुद को महिलाओं का रक्षक सिबित करेंगे। हम जानते हैं

कि महिलाओं का रक्षक बनना आसान नहीं है।

महिला आरक्षण की आड़ में खेल : खरगे

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इंडिया ब्लॉक के सांसद %महिला विरोधी नहीं हैं%। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ एनडीए सरकार सत्ता हासिल करना चाहती है ताकि सदन में साधारण बहुमत से किसी भी परिसीमन कानून को पारित या संशोधित किया जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक और परिसीमन विधेयक का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें परिसीमन का प्रावधान है।

संसद परिसर से मीडिया को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा कि हम महिला विरोधी नहीं हैं और हम लंबे समय से एक तिहाई महिला आरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। हमने सर्वसम्मति से 2023 के संशोधन का समर्थन किया और उसे पारित कराया। हालांकि, इसकी आड़ में उन्होंने एक और संशोधन पेश किया, जिसमें परिसीमन का प्रावधान जोड़कर महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों को समेकित कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा संविधान की संरचना को बदलना चाहती है और कार्यपालिका शक्ति को अपने हाथों में लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि इन तीनों विधेयकों को एक साथ लाकर वे सत्ता हासिल करना चाहते हैं ताकि किसी भी परिसीमन कानून को साधारण बहुमत से सदन में पारित और संशोधित किया जा सके... आपको यह 543 सदस्यों के भीतर करना चाहिए।

मिडिल ईस्ट तनाव से 50 दिन में 50 अरब डॉलर का घाटा

नईदिल्ली। मिडिल ईस्ट में लगभग 50 दिनों से तनाव देखने को मिला। इसका असर दुनियाभर के तेल और गैस सप्लाई पर भी पड़ा। करीब 50 अरब डॉलर (4.63 लाख करोड़ रुपए) का कच्चा तेल बाजार तक पहुंच चुका है। एकस्पर्ट के अनुसार, इस संकट का असर सिर्फ अभी नहीं बल्कि आने वाले कई महीनों और सालों तक महसूस किया जाएगा, क्योंकि सप्लाई में आई यह कमी जल्दी पूरी होना मुश्किल है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि लेबनान में हुए युद्धविराम समझौते के बाद होर्मुज स्ट्रेट फिर से खोल दिया गया है। Kpler के आंकड़ों के अनुसार, फरवरी के अंत में शुरू हुए इस संकट के बाद से ग्लोबल मार्केट से 50 करोड़ (500 मिलियन) बैरल से ज्यादा कच्चा तेल और कंडेन्सेट बाहर हो चुका है।

केंद्रीय कर्मचारियों की बह्ले-बह्ले! सरकार ने 2% बढ़ाया डीए

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है है। यह हाइक 1 जनवरी से प्रभावी हो गई है। बता दें कि सरकार साल में दो बार- जनवरी और जुलाई के लिए - महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा करती है। आमतौर पर इसकी अधिसूचना देरी से आती है, अक्सर होली या दिवाली जैसे त्योहारों के आसपास। हालांकि, इस बार महंगाई भत्ता की घोषणा में देरी होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में असंतोष देखने को मिला। पहले महंगाई भत्ता (डीए) की दर मूल वेतन का 58% थी। कैबिनेट के इस फैसले से बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है। वहीं अब सभी की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। डीए में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब प्रस्तावित 8वीं पे-कमीशन के तहत पे-स्ट्रक्चर में व्यापक बदलाव के लिए कर्मचारी संघों का दबाव बढ़ रहा है।

भारत ने बांग्लादेश को हाई-स्पीड डीजल की आपूर्ति की

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत ने मार्च में बांग्लादेश को 22,000 टन हाई-स्पीड डीजल की आपूर्ति की है और सेशेल्स एवं मालदीव से भी उनकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि इन अनुरोधों पर देश की अपनी जरूरतों, उपलब्धता और रिफाइनिंग क्षमता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने मार्च, 2026 में बांग्लादेश को 22,000 टन डीजल की आपूर्ति की और इस महंगाई भत्ता की इसकी आपूर्ति जारी है। जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की हाल में मॉरीशस यात्रा के दौरान तेल एवं गैस आपूर्ति के लिए दोनों सरकारों के स्तर पर समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

स्टेल प्रमुख समाचार

पाकिस्तान ने बांग्लादेश दौरे के लिए टीम का किया ऐलान

इस्लामाबाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मई में बांग्लादेश दौरे के लिए अहम फैसला किया है। पीसीबी ने टेस्ट टीम के लिए नए हेड कोच का ऐलान किया है। साथ ही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 16 सदस्यी टीम की घोषणा भी कर दी है।

पीसीबी ने सरफराज अहमद को टीम का हेड कोच बनाया है। सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था। इसके अलावा उनके कप्तान रहते ही पाकिस्तान ने साल 2017 में चैंपियन ट्रॉफी जीती थी जो उसका आखिरी आईसीसी खिताब है। उनके कोच रहते पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ने एशिया कप भी जीता था।

इसके अलावा पीसीबी ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान भी किया है। टेस्ट टीम की कप्तान शान मसूद के हाथों में ही है। वहीं सेलेक्शन कमेटी ने चार अकैण्ड खिलाड़ियों को टीम में चुना है। अब्दुल्लाह फजल, अमाद बट, अजान आवेस और मोहम्मद गाजी गौरी वो अनकैण्ड खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम में जगह मिली है। टीम कप्तानी में 27 अप्रैल को इकट्ठा होगी। ये कैम्प एक मई तक चलेगा। दो मई को टीम बांग्लादेश के लिए रवाना होगी। दोनों टीमों के बीच पहला मैच आठ से 12 मई के बीच शेर-ए-बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। वहीं दूसरा टेस्ट 16 से 20 मई के बीच सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। पीसीबी ने पूर्व टेस्ट क्रिकेटर अस्म शफीक को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान टीम इस प्रकार है- शान मसूद (कप्तान), अब्दुल्लाह फजल, अमाद बट, अजान आवेस, बाबर आजम, हसन अली, इमाम उल हक, खुर्रम शाहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, मुहम्मद गाजी गौरी, नोमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, सउद शकील और शाहीन शाह अफरीदी।

अवाडा इलेक्ट्रो को आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी

नई दिल्ली। ब्लूकफील्ड समर्थित अवाडा ग्रुप की सौर विनिर्माण इकाई अवाडा इलेक्ट्रो को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये अनुमानित 9,000 से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। नियामक ने शुक्रवार को अद्यतन सूचना में यह जानकारी दी। सूचना के अनुसार इन तीनों कंपनियों को 15 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच नियामक की टिप्पणियां मिलीं। सेबी की शब्दावली में टिप्पणी जारी करने का अर्थ सार्वजनिक निर्गम लाने की अनुमति देना है। अवाडा इलेक्ट्रो ने अक्टूबर में गोपनीय मार्ग से सेबी के पास अपने दस्तावेज जमा किए थे। इस घटनाक्रम से परिचित लोगों के अनुसार कंपनी 9,000 से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रख रही है, जिससे इसका मूल्यांकन 1.10 लाख करोड़ रुपए से 1.3 लाख करोड़ रुपए के बीच हो सकता है।

शंकर अस्वर

होर्मुज जलडमरूमध्य 2026 में भू-राजनीति का केंद्र बन गया है। पिछले दिनों हमने देखा कि जब भी ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों को रोकने या अनुमति देने के लिए अपनी सैन्य ताकत दिखाता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था सहम जाती है। जब भी अमेरिका और ईरान के बीच शब्दों और मिसाइलों का आदान-प्रदान होता है, तो हर धमकी के साथ अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है।

पिछले हफ्ते बैंकों, बीमा कंपनियों और उन देशों को, जो अपने जहाजों को इस मार्ग से गुजारना चाहते थे, एक नई भुगतान प्रणाली के बारे में पता चला। यह प्रणाली ईरानियों ने उन जहाजों के लिए शुरू की है, जो यहां से आवाजाही करना चाहते हैं। इसके तहत दो विकल्प दिए गए हैं। पहला, 20

लाख डॉलर की रकम चीनी युआन में भुगतान करें। दूसरा, 20 लाख डॉलर क्रिप्टोकॉरेंसी में दें। पिछले हफ्ते शनिवार तक, मुश्किल से एक दर्जन जहाज ही यहां से गुजर पाए, जिनमें से कई ईरान से जुड़े हुए थे। फिर अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों से निकलने वाले जहाजों की नाकेबंदी का आदेश दे दिया। खबर है कि कुछ जहाज जलडमरूमध्य को पार कर चुके हैं। युआन या क्रिप्टोकॉरेंसी में जमा की गई रकम का अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। ईरान द्वारा दी गई चुनौती ने एक बार फिर डॉलर के पतन की चर्चाओं को जन्म दिया है।

दुनिया की रिजर्व मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की भूमिका की नींव 20 जुलाई, 1974 को सऊदी अरब में हुए एक समझौते के साथ पड़ी थी। अमेरिका ने सऊदी अरब को आपसी लेनदेन का एक प्रस्ताव दिया। इसमें कहा गया कि सऊदी



अरब कच्चे तेल के हर बैरल का भुगतान अमेरिकी डॉलर में करेगा, और इसके बदले में अमेरिकी सरकार सऊदी शासन को सुरक्षा की गारंटी देगी। चतुर भू-राजनीति को चतुर अर्थशास्त्र का सहारा मिला। तेल की वैश्विक मांग और डॉलर के वैश्विक मूल्य-निर्धारण ने डॉलर के वर्चस्व को और भी मजबूत कर दिया। पाँच दशकों बाद, संप्रदाय-आधारित वर्चस्व और वैश्विक मुद्रा के विचार अपनी चमक खो रहे हैं। भू-राजनीति वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को नए सिरे से गढ़ रही है। चीन कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा

बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहे हैं। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए सोना संपत्ति का सबसे बड़ा भंडार बन गया है और उसने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी से इसके मूल्य और खरीद, दोनों में ही तेजी आई है। केंद्रीय बैंक हर साल लगभग 1,000 टन सोना जमा कर रहे हैं। सोने की इस खरीदारी की वजह से रिजर्व में डॉलर का औसत हिस्सा 12 प्रतिशत कम हो गया। डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए एफए और छिपे, दोनों तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसकी मुख्य वजहें हैं- अमेरिका की ममाननी नीतियों से जुड़े जोखिम को कम करना और निवेश में विविधता लाना। रूस के 300 अरब डॉलर के रिजर्व को फ्रीज किए जाने के बाद, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं अब दूसरे विकल्पों, यानी 'किसी भी आपात स्थिति के लिए' वैकल्पिक उपायों की गुंजाइश बना रही हैं।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर उत्कृष्ट प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर मिले दो प्रतिष्ठित पुरस्कार

■ यह सम्मान निरंतर सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का परिणाम: स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल



परफार्मिंग लार्ज स्टेट के रूप में हार्ड ट्रिगर एफिकेसी और टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ सस्पेंसियस क्लेम्स श्रेणियों में चयनित किया गया।

हार्ड ट्रिगर एफिकेसी श्रेणी में राज्य ने संदिग्ध क्लेम की पहचान एवं उनके प्रभावी विश्लेषण में उल्लेखनीय दक्षता प्रदर्शित की है। उन्नत आईटी आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली तथा सुदृढ़ ऑडिट

व्यवस्था के माध्यम से अनियमितताओं की समयबद्ध पहचान सुनिश्चित की गई है। वहीं टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ सस्पेंसियस क्लेम्स श्रेणी में राज्य ने संदिग्ध दावों के त्वरित निपटान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। निधार्सित समय-सीमा के भीतर क्लेम की जांच, निर्णय एवं निष्पादन सुनिश्चित कर पारदर्शिता एवं जवाबदेही को मजबूत किया

गया है। राज्य में क्लेम ऑडिट तंत्र को सशक्त बनाने, ट्रिगर-आधारित निगरानी प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने तथा अस्पतालों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के कारण संदिग्ध प्रकरणों के निराकरण में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। इसके परिणामस्वरूप क्लेम प्रोसेसिंग की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है तथा

अनावश्यक विलंब में कमी आई है, जिससे योजना के लाभार्थियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेश के राज्य को मिली इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य तंत्र की प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और निरंतर सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हम प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। यह पुरस्कार हमारे स्वास्थ्यकर्मियों, प्रशासनिक टीम और सहयोगी संस्थानों के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। हम भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते रहेंगे।

सीएम साय ने सुना पीएम मोदी का संबोधन



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ने शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम प्रसारित संबोधन का श्रवण किया। यह संबोधन नारी शक्ति वंदन लेकर देशभर में चर्चा जारी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, रायपुर की महापौर मीनल चौबे और महिला बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा सहित अन्य महिला जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। सभी ने प्रधानमंत्री के

संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना। बताया गया कि इस दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई और महिलाओं के राजनीतिक व सामाजिक सशक्तिकरण के मुद्दे को प्रमुखता दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने इस विषय पर अपने विचार भी साझा किए और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां लागू की जा

रही हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है।

कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया गया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अधिक अवसर देना है, जिससे वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा सकें। इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ेगी। अधिकारियों के अनुसार, इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर लिए जा रहे महत्वपूर्ण निर्णयों और नीतियों से जोड़ना है। इससे समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और लोगों की भागीदारी भी बढ़ती है।

बिलासपुर रेलवे अब राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा क्रांति का सक्रिय हिस्सा बन चुका है : रेलमंत्री वैष्णव

रायपुर –बिलासपुर । केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में सुरक्षा उपायों पर एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर अब राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा क्रांति का सक्रिय हिस्सा बन चुका है। छत्तीसगढ़ की रेल यात्रा अब पहले से कहीं अधिक सुरक्षित, आधुनिक और विश्वसनीय हो रही है। राज्य के प्रमुख जिलों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा आदि को कवर करती है और यहां मानवरहित लेवल क्रॉसिंग पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं।

रेल मंत्री ने बताया कि पूरे भारतीय रेलवे में गंभीर रेल दुर्घटनाओं की संख्या 2014-15 के 135 से घटकर 2025-26 में मात्र 16 रह गई है। यानी लगभग 89 प्रतिशत की भारी कमी आई है। कॉन्सीक्रेशियल एक्सीडेंट इंडेक्स भी



0.11 से गिरकर 0.01 पर आ गया है, जो यूरोपीय संघ जैसे विकसित रेल सिस्टम से भी बेहतर है। सुरक्षा पर खर्च 2013-14 के 39 हजार 200 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 1 लाख 20 हजार 389 करोड़ किया गया है।

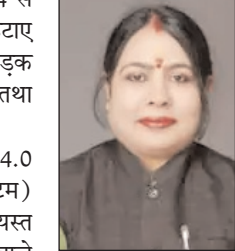
छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मंत्री ने एसईसीआर की उपलब्धियों को विशेष रूप से उल्लेखनीय बताया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय बिलासपुर में है और जो राज्य के प्रमुख जिलों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा आदि को कवर करती है, में मानवरहित लेवल

क्रॉसिंग पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में एसईसीआर ने 18 रोड ओवर ब्रिज और 27 रोड अंडर ब्रिज का निर्माण पूरा किया, जिससे 34 से अधिक लेवल क्रॉसिंग हटाए गए। इससे रेल और सड़क यातायात दोनों सुरक्षित तथा सुगम हुआ है।

स्वदेशी कवच 4.0 (ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम) का विस्तार एसईसीआर के व्यस्त कोयला और खनिज ढुलाई वाले रूटों पर तेजी से हो रहा है। यह तकनीक लोको पायलट की गलती या ओवर स्पीडिंग को स्थािति में ट्रेन को स्वतः ब्रेक लगा देती है। ट्रेक की गुणवत्ता में सुधार, 60 किग्रा भारी पटरियों, लंबे वेल्डेड रेल और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग से पटरी फ्रैक्चर में 92 प्रतिशत और वेल्ड फेलियर में 93 प्रतिशत की कमी आई है।

कांग्रेस ने हमेशा मातृशक्ति का अपमान किया है : विभा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी ने कहा है कि नारी शक्ति वन्दन अधिनियम का विरोध कर कांग्रेस पार्टी ने देश की मातृशक्ति का अपमान किया है। इसके विरोध में देश की मातृशक्ति कांग्रेस सहित समचे विपक्षी दल के लोगों के खिलाफ एक उग्र जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अवस्थी ने कहा कि कांग्रेस के महिला विरोधी चेहरे को देश की जनता के सामने लाने के लिए प्रदेश, संभाग, जिलों में प्रेसवार्ता की जाएगी। नारी शक्ति वन्दन अधिनियम का विरोध करने पर प्रदेश की महिलाएँ उग्र हो चुकी हैं। श्रीमती अवस्थी ने बताया कि 20 एवं 21 अप्रैल को प्रदेश में जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकालकर कांग्रेस की महिला विरोधी चेहरे को उजागर किया जाएगा। इसके साथ ही 23 एवं 24 अप्रैल को जन आक्रोश महिला सम्मेलन का आयोजन रखकर महिला हितैषी बिल का विरोध करने पर कांग्रेस पार्टी एवं समूचे विपक्ष का चेहरा बेनकाब किया जाएगा।



महिला मोर्चा की जन आक्रोश पदयात्रा 20 अप्रैल को दोपहर 03 बजे इंडोर स्टेडियम से शुरू होगा। नारी जन आक्रोश पदयात्रा इंडोर स्टेडियम से लेकर सुभाष स्टेडियम तक होगी। पदयात्रा के बाद सुभाष स्टेडियम में एक बड़ी सभा होगी। सभा में प्रदेश की सभी महिला सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, महापौर, नगर पंचायत अध्यक्ष ङ्क उपाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष विभिन्न समाजिक संगठन, सहित महिला मोर्चा की कार्यकर्ता शामिल होगी।

सरकार को गरीब बच्चों की शिक्षा की चिंता नहीं: बैज

रायपुर। सरकार को गरीब बच्चों की शिक्षा की चिंता नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आर.टी.ई में बच्चों की भर्ती का मामला अधर में पड़ा हुआ है। सरकार बच्चों का एडमोशन हो इसलिये कोई प्रयास नहीं कर रही है। जबकि बच्चों का एडमोशन स्कूलों में हो, शिक्षा के



अधिकार के तहत अधिकांश उनको शिक्षा प्राप्त हो यह सुनिश्चित करने की अब जवाबदारी राज्य सरकार की है। साय सरकार उदासीन बनी हुई है। सरकार हठ धर्मिता छोड़े तथा निजी स्कूलो से बातचीत कर मामले का समाधान निकाले। कांग्रेस पार्टी मांग

करती है कि सरकार तुरंत प्राइवेट स्कूल के प्रतिनिधियों से बात करे, गतिरोध समाप्त करें, ताकि बच्चों का एडमिशन हो सके। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने गरीबों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने आर.टी.ई. लेकर आई थी, भाजपा सरकार उसमें अवरोध पैदा कर रही। निजी स्कूल वालो की मांग पर विचार करें, उनका कहना है वर्षो से उनकी फीस नहीं बढ़ाई गयी है जबकि खर्चें बढ़ गये है। 11 सालो से कोई बढोत्तरी नहीं की गई है। सरकार उनकी मांगो को मानने के बजाय धमकी चमकी पर उतर आई है। निजी स्कूलों ने भी सरकार के खिलाफ आंदोलनरत है।

महिला आरक्षण को लेकर भाजपा भ्रम फैला रही : शुक्ला

रायपुर। भाजपा द्वारा महिला आरक्षण को लेकर लगातार झूठा भ्रम फैलाया जा रहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया, इसलिए संसद में बिल पास नहीं हो सका। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ



बोल रही है, महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023) 106वां संविधान संशोधन 2023 में संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर हस्ताक्षर कर चुकी है तथा यह कानून भी बन चुकी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग

के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने 16 अप्रैल 2026 को जो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया 131 वां संविधान संशोधन अधिनियम इसमें महिला आरक्षण के संदर्भ में नहीं भाजपा महिला आरक्षण को मुखौटा बनाकर परिसीमन संशोधन बिल तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल को पास करवाना चाहती थी। संसद में जो विधेयक गिरा उसमें इस विधेयक में लोकसभा परिसीमन की सीटें 850 करने का प्रस्ताव था। राज्यों में 815 सीटें तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 35 सीटें। परिसीमन विधेयक- जिसमें परिसीमन के लिये 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात की गयी थी।

केन्द्रीय मंत्री को पत्र लिखकर न्याय मांगना पड़ रहा: ठाकुर

रायपुर। केन्द्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले के पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार में पीएम आवास तोड़े जा रहे हैं। खासकर के एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के आवास को चिन्हित कर तोड़ा जा रहा है। कबीरधाम जिला में एससी वर्ग के पीएम आवास को बिल नोटिस तोड़ दिया गया। परिजनों के मोबाइल छीन लिया गया। ये तो सरासर गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। केन्द्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले को, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पीड़ित परिवार के लिए न्याय मांगना पड़ रहा है। मोदी की



गारंटी थी 18 लाख नया आवास देने का यहां तो उज्जटी गंगा बह रही है, हितग्राहियों को पीएम आवास मिल नहीं रहा व बल्कि कांग्रेस सरकार में जिन्हें पीएम आवास मिला उसे ही तोड़ जा रहा है। भाजपा सरकार बनने के बाद गरीबों के मकान, दुकान को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। इनका मुकसद गरीबों को घर से बेधर करना है, इनके बुलडोजर से पीएम आवास भी नहीं बच पा रहे है। पीएम आवास तोड़ने की घटनायें लगातार हो रही है जगदलपुर, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर सहित सभी जिलों में पीएम आवास तोड़ने की घटना हुई है। ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है।

उर्वरक की व्यवस्था में सरकार की तैयारी पूरी नहीं : वर्मा

रायपुर। खरीफ के लिए खाद उपलब्ध करवा पाने के मामले में सरकार ने ठोस प्रयास शुरू नहीं किया है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि कृषि मंत्री केवल मीडिया में बयान देकर अपने कर्तव्य की पूर्ति समझ लिए है। सरकार ने अभी तक उर्वरकों की व्यवस्था के बारे में निश्चित



बनी हुई है। अभी तक सरकार को किसानों की जरूरत के अनुसार सोसायटियों से मांग का डाटा एकत्रित कर सभी सोसायटियों में खाद पहुंचाना शुरू कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार बताये कि इस वर्ष कितने उर्वरकों की जरूरत का आंकलन किया गया तथा सरकार के पास कितनी उपलब्धता की व्यवस्था की गयी है? भाजपा की सरकार आदतन किसान विरोधी है, पिछले खरीफ सीजन में खाद का संकट छत्तीसगढ़ के किसानों ने भोगा हैं, अब फिर वही स्थिति बन रही है, सरकार के संरक्षण में नकली खाद, अमानक खाद, नैनो यूरिया के नाम पर गुणवत्ताहीन खान लेने किसानों को मजबूर किया गया, ऐसे ही झूठे दावे सरकार ने पिछले करीब सीजन में भी सरकार करती रही और किसान खाद के लिए दर-दर भटकते रहे, यूरिया और डीएपी का स्टॉक डिमांड के आधा भी उपलब्ध नहीं कर पाई सरकार।

महतारी वंदन में महिलाओं के नाम काटना चाह रही: वंदना

रायपुर। महतारी वंदन में केवाईसी का बहाना कर सरकार महिलाओं का नाम काटना चाह रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के समय सभी विवाहित महिला को 1000 रू. प्रतिमाह देने का वादा किया था। सरकार के आने के बाद भाजपा



अपने वादे से पलट गयी। सभी विवाहित के स्थान पर इंकमटैक्सपेयी परिवार, सरकारी नौकरी परिवार की बंदिशे लगाकर महिलाओं को अपात्र घोषित किया। महतारी वंदन की पहली किस्त में 75 लाख महिलाओं को राशि दी गयी। धीरे-धीरे हर माह सरकार ने कटौती कर दिया। आखिरी में लगभग 69 लाख महिलाओं को ही राशि मिल पाई। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि अब सरकार केवायसी का बहाना बनाकर और महिलाओं को महतारी वंदन के लाभ से वंचित करना चाह रही है। यह सरकार की वादाखिलाफी है। सरकार प्रदेश में निवासरत हर विवाहित महिला को छत्तीसगढ़ की मतदाता है, या जिसका आधार कार्ड छत्तीसगढ़ का है, उसे महतारी वंदन की राशि दे। सरकार अप्रैल, मई और जून की भीषण गर्मी में केवाईसी के नाम पर महिलाओं को परेशान करना चाह रही है।

सरकार का ‘चावल उत्सव’ बना ‘अव्यवस्था उत्सव’ : आम आदमी पार्टी

रायपुर। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश के लगभग 73 लाख राशन हितग्राहियों को तीन माह का चावल एकमुश्त बांटने के फैसले को लेकर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष (कर्मचारी विंग) विजय कुमार झा, प्रदेश प्रवक्ता जयदीप मिश्रा, प्रदेश मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मी और प्रदेश सोशल मीडिया सह प्रभारी मिथलेश साहू द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस निर्णय को पूरी तरह अव्यवस्थित और जनविरोधी बताते हुए कहा कि सरकार का तथाकथित चावल उत्सव अब जमीनी स्तर पर अव्यवस्था उत्सव में बदल चुका है।पार्टी पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में



कहा कि बिना पर्याप्त तैयारी के तीन माह का चावल एक साथ वितरण करने का निर्णय जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राशन दुकानों में न तो पर्याप्त स्टॉक है और न ही ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सही है, जिससे हितग्राहियों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

राशन दुकानों में तीन माह के हिसाब से चावल उपलब्ध नहीं, ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की भारी कमी,

सप्लाई बाधित, अप्रैल माह का भंडारण अधूरा, मई-जून का स्टॉक नहीं पहुंचा, हितग्राहियों को कई बार खाली हाथ लाटिया पड़ रहे,एकमुश्त चावल ले जाने में 100-150 रुपये तक अतिरिक्त खर्च, छोटे घरों में चावल के सुरक्षित भंडारण की समस्या, दुकानदार और हितग्राही दोनों परेशान, पार्टी नेताओं ने कहा कि सरकार ने राशन दुकानदारों पर भी बिना संसाधन के अतिरिक्त जिम्मेदारी डाल दी है।